



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1941]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2010/भाद्र 24, 1932

No. 1941]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2010/BHADRA 24, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

का.आ. 2291(अ).—दिनांक 19 फरवरी, 1991 में केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 114(ई), के अनुसार तटीय विनियमन जोन (जहां इसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा जाएगा) को अधिसूचित किया था तथा इन जोनों की सुरक्षा करने के लिए एवं उद्योगों को लगाने, उसके विस्तार करने, उसके संचालन इत्यादि हेतु कुछ नियमों को भी लागू किया;

और जबकि 1993 के रिट पिटिशन संख्या 664 को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल, 1993 में केन्द्र सरकार एवं तटीय राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि 'भारत में 6000 किमी का तटीय विस्तार है। यह उन तटीय राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों का उत्तरदायित्व है जहां पर यह तटीय विस्तार है, कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि वहाँ इस अधिसूचना को बनाया व लागू किया गया है;

और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए तटीय राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने दिनांक 27 सितम्बर 1996 में निहित परिस्थितियों व परिवर्तनों को शामिल करते हुए तटीय जोन प्रबंधन योजना का निर्माण किया;

और जबकि विभिन्न समितियों, न्यायिक घोषणाओं, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, केन्द्र सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों व सामान्य जनता द्वारा दी गयी संस्तुतियों को समय-समय पर इस अधिसूचना में शामिल करके संशोधित किया गया;

और जबकि तटीय क्षेत्रों के सतत् विकास तथा तटीय संसाधनों के संरक्षण हेतु इस अधिसूचना के प्रभावी क्रियान्वयन में लगातार आ रही कठिनाईयों को देखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसमें पर्यावरणीय कानून, समुद्री जैवविविधता, समुद्री भूविज्ञान, पर्यावरणीय आर्थिकी, सामाजिक आर्थिकी, पुरस्नेदी, तटीय अभियांत्रिकी, शहरी नियोजन तथा समुद्री मत्स्य पालन से जुड़े क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया। इस समिति ने पूर्ववर्ती समितियों के निश्कर्शों एवं सिफारिशों, न्यायिक घोषणाओं, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिसूचना तथा इसमें किए गए संशोधनों की व्यापक समीक्षा करने के लिए तथा आवश्यक होने पर तटीय जोन प्रबंधन के सुस्थापित वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुरूप तटीय विनियमन ढांचा तैयार करने के क्रम में उपयुक्त संशोधनों पर सुझाव दिये।

और जबकि उपर्युक्त विशेषज्ञ समिति ने 14 फरवरी 2005 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें समिति ने मौजूदा विनियमन और संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा संरक्षण के अन्तरालों को भरने और तटीय संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाने हेतु तटीय क्षेत्र के सजीव व निर्जीव संसाधनों को बढ़ावा देना; तटीय आबादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तथा विकट मौसम एवं भू-वैज्ञानिक घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों से अवसंरचनाओं की सुरक्षा तथा द्वीपों पर बसने वाली जनसंख्या की आजीविका को सुदृढ़ करने की सिफारिशें की थीं।

और जबकि केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2008 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा 1 और खंड (अ) के अंतर्गत आदेश संख्या 1761(ई) को पारित करते हुए एक ड्राफ्ट अधिसूचना का निर्माण किया और इसके द्वारा प्रभावित होने वाली जनता से सुझावों व आपत्तियों को आमंत्रित किया,

और जबकि केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस ड्राफ्ट अधिसूचना पर जनता द्वारा बहुत अधिक संख्या में सुझाव व आपत्तियां प्राप्त हुई जिसका निरीक्षण प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया;

और जबकि इस ड्राफ्ट तटीय प्रबंधन जोन अधिसूचना, 2008 पर प्राप्त टिप्पणियों व विभिन्न हितधारकों के साथ किए गए परामर्शों पर प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत अध्ययन के पश्चात् 16 जुलाई, 2009 को 'अंतिम सीमा' नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में ड्राफ्ट तटीय प्रबंधन जोन अधिसूचना, 2008 को पारित न करने व सी. आर.जेड. अधिसूचना, 1991 को मजबूती प्रदान करने की संस्तुति दी गयी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए सी.एम.जेड अधिसूचना, 2008 को पारित न करने का फैसला किया;

और जबकि विशेषज्ञ समिति ने यह भी बताया कि आज भारतीय तट पहले से दोगुने खतरे को महसूस कर रहा है। जहां एक ओर यह क्षेत्र औद्योगिक एवं शहरी विकास के कारण अत्यधिक दबावों का सामना कर रहा है वहीं दूसरी ओर यह जलवायु परिवर्तन के खतरों—तूफानी चक्रवातों व समुद्री जल स्तर के बढ़ने से भी काफी खतरे में होगा। इन तटीय क्षेत्रों व यहां के निवासियों की सुरक्षा से संबंधित सभी खतरों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि तटीय क्षेत्र मछुआरा समुदाय का निवास स्थान है। यह समुदाय एक ओर संरक्षण प्रयासों व दूसरी ओर विकासात्मक गतिविधियों से उत्पन्न दोहरे खतरों का सामना कर रहा है। भविष्य में बनने वाली तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी नीतियों को इन क्षेत्रों में मौजूद पारितंत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा तथा यहां के निवासियों की आजीविका को सुरक्षित करने संबंधित प्रयासों व तरीकों को परिवर्तित करने वाला होना चाहिए। यह एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त समिति ने देश में तटीय जोन प्रबंधन तरीकों को मजबूती प्रदान करने के लिए भी कई संस्तुतियां दी हैं;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट व प्राप्त संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2009 से मार्च 2010 तक मछुआरा समुदायों, स्थानीय समुदायों व गैर सरकारी संगठनों के साथ कई परामर्श बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों का आयोजन पर्यावरण शिक्षण केन्द्र (सी.ई.ई.) द्वारा किया गया, जिसने 25 मार्च 2010 को इस परामर्श प्रक्रिया से संबंधित रिपोर्ट को प्रस्तुत किया;

और जबकि केन्द्र सरकार ने ' फाइनल फंटियर ' नामक रिपोर्ट तथा सी.ई.ई. द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जिसमें तटीय क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों को वहां के जनसांख्यिकीय दबावों, भौगोलिक तथा पारिस्थितिकीय विशिष्टताओं पर विशेष विचार किया गया था और जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी और अंग्रेजी सहित 9 स्थानीय तटीय भाषाओं गुजराती, कोंकणी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू, तमिल, उड़िया और बंगाली भाषाओं में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2010 पर मसौदा पूर्व टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 30 दिनों की अवधि दी गई थी;

और जब कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्र और राज्य सरकारों सहित जनता, गैर सरकारी संगठनों आदि से तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2010 के मसौदे पर अनेक टिप्पणियां प्राप्त हुई थी;

और जबकि केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त परामर्श प्रक्रियाओं के निष्कर्षों व प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन समिति द्वारा 16 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत संस्तुतियों से संबंधित रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 2 की उपखंड 1 और खंड (अ) के अंतर्गत निम्न प्रस्ताव को पारित करने का विचार किया। यह प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी, 1991 में दिए गए आदेश संख्या 114(ई) विस्थापन से संबंधित अधिसूचना के संदर्भ में दिया गया था। इस अधिसूचना में देश के तटीय विस्तार के संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991, आदेश संख्या 114(ई), दिनांक 19 फरवरी, 1991 के स्थगन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन सभी कार्यकलापों, जोकि इस अधिसूचना के लागू होने से पहले तक हुए थे, को शामिल नहीं किया गया था। केन्द्र सरकार ने लोकहित में इस अधिसूचना को पुनः प्रकाशित करने का निर्णय लिया है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना के प्रारूप पर केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि समाप्त होने की तारीख को और इसके बाद विचार किया जाएगा;

और जबकि कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचना के प्रारूप में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति तथा सुझाव देने का इच्छुक है तो वह इसके लिए विशेष रूप से निर्धारित अवधि में सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 को डाक द्वारा लिखित रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-मेल पता: secy@menf.nic.in द्वारा ऐसा कर सकता है।

प्रस्ताव प्रारूपतटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.), 2010

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 2 की उपखंड 1 और खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानीय समुदायों को आजीविका सुनिश्चित करने, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण और इसके विषिष्ट पर्यावरण व समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा व संरक्षण करने तथा तटीय क्षेत्रों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं व ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित टिकाऊ तरीके से होने वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के तटीय विस्तार व आसपास के जल क्षेत्रों, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों तथा लक्ष्यद्वीप तथा समुद्री क्षेत्र जो इन द्वीपों को चारों ओर से घेरे रहती है को छोड़कर, तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) के रूप में घोषित करती है और इस सी आर जेड में किसी भी प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने, उसके विस्तार से जुड़ी प्रक्रियाओं के साथ-साथ उसके संचालन तथा खतरनाक वस्तु (उपयोग, प्रबंधन एवं आयात-निर्यात) नियम, 2009 में सूचीबद्ध खतरनाक वस्तुओं के विनिर्माण या हथालन या निस्तारण करती है।

2. अतः अब पर्यावरण सुरक्षा नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस आधार पर सम्पूर्ण शक्तियों को लेते हुए केन्द्र सरकार ने निम्न क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) घोषित करती है तथा इस अधिसूचना के लागू होने के दिनांक से इन क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने, उसके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं इत्यादि को सी.आर.जेड. में प्रतिबंधित करती है :

- (i) उच्च ज्वार रेखा (एच.टी.एल.) से लेकर समुद्र की ओर अभिमुख 500 मीटर के भू-क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- (ii) सी.आर.जेड. उन क्षेत्रों पर भी लागू होता है जो एच.टी.एल. से लेकर ज्वार से प्रभावित जलाशयों, जोकि समुद्र से जुड़ी हुई हैं, की ओर अभिमुख 100 मीटर के भू-क्षेत्र के मध्य स्थित है। वह दूरी जहां तक ज्वार से प्रभावित जलाशयों के आसपास विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित किया जाना है और इस दूरी का निर्धारण वर्ष के शुष्क काल में लवणीयता की मात्रा को 5 पार्ट्स प्रति हजार (पी.पी.टी.) को आधार मानकर किया जाएगा तथा ज्वार से प्रभावित होने वाली दूरी को तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं (सी.जेड.एम.पी.) के अनुसार पहचान कर उसका निर्धारण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस उप पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ ज्वार से प्रभावित जलाशयों का अर्थ है

समुद्र, खाड़ी, एश्च्यूरी, झील, बैकवाटर, लगून समुद्र या कीक से जुड़े जलाशय इत्यादि।)

- (iii) हेजार्ड रेखा या खतरे की रेखा और तट की ओर के एच.टी.एल. से 500 मीटर तक के क्षेत्र के मध्य स्थित भू-क्षेत्र । हेजार्ड रेखा या खतरे की रेखा का अर्थ है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वर्षद्धि एवं तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया सीमांकन ।
- (iv) एच.टी.एल. एवं निम्न ज्वारीय रेखा (एल.टी.एल.) के मध्य स्थित भू-क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसे इण्टरटाइडल जोन कहा जाएगा ।
- (v) सामान्य समुद्र के लिए एल.टी.एल. एवं क्षेत्रीय जल सीमा (12 नॉटिकल मील) के मध्य स्थित भू-क्षेत्र व ज्वार से प्रभावित जलाशयों के लिए किनारे पर एल.टी.एल. से एल.टी.एल. के बीच के क्षेत्र हैं ।

2.1 इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, एच.टी.एल. का अर्थ है वह भू-क्षेत्र जहां तक गर्मियों के मौसम में होने वाले ज्वार प्रक्रियाओं के कारण जल अधिकतम ऊँचाई तक पहुँचता है। पूरे देश में एच.टी.एल. का एक समान निर्धारण किया जाना चाहिए। इसका निर्धारण संलग्नक-1 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

3. सी.आर.जेड. के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियाँ:—सी.आर.जेड. के अंतर्गत निम्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है:—

- (i) नए उद्योगों को स्थापित करने व उसके विस्तार से संबंधित गतिविधियाँ, निम्न को छोड़कर,—

अ. वे उद्योग जिन्हें जल या वाटर फ्रन्ट अथवा फोरशोर सुविधाओं की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है;

स्पष्टीकरण : किनारे संबंधी सुविधाओं का अर्थ है इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुमेय सुविधाएं और उनके लिए प्रचालन हेतु वाटर फ्रंट जैसे पत्तन और हार्बर, जेट्टी, क्वेस, वहावर्स, क्षरण नियंत्रण उपाय, ब्रेक वाटर, पाइप लाइनें, लाइट हाउस, समुद्री सुरक्षा सुविधाएं, तटीय पुलिस थानों आदि की आवश्यकता होती है ।

ब. परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं;

स. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रदूषण रहित उद्योग तथा सी.आर.जेड. में स्पेशल इकोनोमिक जोन (एस.ई.जेड.) के अंतर्गत आने वाली अन्य औद्योगिक इकाईयां;

द. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति उत्पादन की सुविधाएं तथा सी.आर.जेड.—। (i) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में डिसेलिनेशन संयंत्रों की स्थापना;

य. नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे के निर्माण प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, परन्तु इस गतिविधि को शामिल करने से पूर्व इससे जुड़ी वैज्ञानिक अध्ययनों, जिसमें नवी मुम्बई क्षेत्र के तटीय पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने से संबंधित पर्याप्त साधनों को शामिल किया गया हो, को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

(ii) तैलीय उत्पादों के निर्माण या संग्रहण अथवा खतरनाक वस्तुओं के निस्तारण की प्रक्रिया जैसा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश संख्या 594(ई.) दिनांक 28 जुलाई 1989, आदेश संख्या 966(ई.) दिनांक 27.11.1989 एवं जी.एस.आर. 1037(ई.) दिनांक 5 दिसम्बर 1989 में लिखित है, निम्न को छोड़कर,—

अ. खतरनाक वस्तुओं का जहाज से बंदरगाह, टर्मिनल एवं रिफाइनरी इत्यादि स्थानों से स्थानान्तरण;

ब. इस अधिसूचना के संलग्नक—II में दिए गए दिषा-निर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों व तरल प्राकृतिक गैस के आवागमन व भंडारण संबंधी सुविधाएं तथा सी.आर.जेड.—

(i) के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में तरल प्राकृतिक गैसों के पुनः गैसीकरण से संबंधित सुविधाएं। इन क्षेत्रों को निर्धारित करने से पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तैल उद्योग सुरक्षा निदेशालय व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिषा-निर्देशों के अनुसार वहां सुरक्षा संबंधी नियम हैं या नहीं इसका निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ-साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किए गए सुधारों को लागू करने की परिस्थितियां भी शामिल हैं।

इस अधिसूचना में, उर्वरकों तथा इसके निर्माण में अमोनिया, फॉस्फोरिक अम्ल, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि जैसे कच्चे माल को प्राप्त करने व उसके भंडारण से संबंधित सुविधाओं को केवल सी.आर.जेड.— I (i) के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिए, ऐसा प्रस्तावित है।

(iii) मत्स्य प्रसंस्करण इकाईयों जिसमें वेयरहाउसिंग (हैचरी या अण्डजनन केन्द्रों व पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में मछलियों को प्राकृतिक रूप से सुखाने की प्रक्रिया) शामिल है, की स्थापना तथा उसका विस्तार :

बशर्ते कि पहले से मौजूद मत्स्य प्रसंस्करण इकाईयां (19.2.1991 से पहले वाली) यदि आधुनिकता के उद्देश्य से विस्तार करना चाहती हैं तो वे 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्लिन्थ क्षेत्र

को ले सकती हैं जिसका उपयोग मौजूदा फलोर स्थान सूचकांक या फलोर क्षेत्र अनुपात मानकों के अनुसार अतिरिक्त कलपुर्जों व प्रदूषण को कम करने वाले उपकरणों को लगाने के लिए कर सकती हैं और बशर्ते कि प्लिन्थ क्षेत्र को, समुद्र की ओर पहले से मौजूद मत्स्य प्रसंस्करण इकाईयों की ओर नहीं होंगे तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस. पी.सी.बी.) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पी.सी.सी.) से अनुमोदन के अधीन होंगे।

(iv) अपशिष्ट एवं उत्प्रवाहों के निस्तारण से संबंधित इकाईयों या प्रणालियों की स्थापना एवं विस्तार संबंधी गतिविधियां, निम्न को छोड़कर जहां इस सुविधा की आवश्यकता होती है,—

अ. जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिसमें उपचारित उत्प्रवाह को जलाशयों में निस्तारित करने की बात का वर्णन है;

ब. तेज जल प्रवाह नालियां

स. सी.आर.जेड.—। के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों अर्थात् सी.आर.जेड. से संबंधित क्षेत्रों में स्थित होटलों व समुद्र तट रिसॉर्टों से निकलने वाले अपशिष्टों एवं उत्प्रवाहों का उपचार व उपचारित अपशिष्टों एवं उत्प्रवाहों का निस्तारण;

(v) उद्योगों, शहरों व कस्बों तथा अन्य मानवीय आवासों से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्टों एवं उत्प्रवाहों का निस्तारण संबंधी गतिविधियां। यदि ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं तो उन्हें रोकने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को इस अधिसूचना के लागू होने से दो वर्षों के अंतर्गत योजनाएं बनायी जानी चाहिए,

(vi) भू-भरण के उद्देश्य से शहर व कस्बे से निकलने वाले अपशिष्टों तथा औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, प्लाई ऐस का निस्तारण; यदि ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं तो उन्हें रोकने के लिए इस अधिसूचना के लागू होने से पहले साल के अंतर्गत इसे बंद करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए।

(vii) राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकारों को 3 (अ) एवं 3(अप) के लिए एक कार्यवाही योजना का निर्माण करना होगा तथा तटीय क्षेत्रों एवं जलाशयों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पर्याप्त बजट निर्धारित करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकारों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को, इस अधिसूचना के लागू होने से ठीक 6 महीने के भीतर एक कार्यवाही योजना प्रस्तुत करनी होगी।

(viii) इस योजना को क्रमवार तरीके से प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकारों को लागू करना होगा।

(ix) इस कार्यवाही योजना का अनुश्रवण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को करना होगा।

(x) भू-सुधार, समुद्री जल को बांधना या उसके प्राकृतिक प्रवाह को बिगाड़ने से संबंधित गतिविधियां, निम्न को छोड़कर,—

अ. अग्रतट सुविधाओं में सुधार करने के लिए की जा रही निर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गतिविधियां, जैसे बंदरगाह, हार्बर, जेट्टी, घाट, जल मंच या स्लिपवे, पुल, सीलिंग इत्यादि एवं अन्य सुविधाएं जोकि अत्यंत आवश्यक है एवं अधिसूचना में वर्णित हैं।

ब. क्षरण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्य, जोकि वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित हो जिसमें ई.आई.ए. भी शामिल है

स. जलमार्गों, चैनलों एवं बंदरगाहों की देखरेख या उनकी साफ-सफाई जोकि वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित हो जिसमें ई.आई.ए. भी शामिल है

द. बलुई टीलों को बनने से रोकने, ज्वार नियंत्रकों के प्रतिस्थापन, तेज जल प्रवाह नालियां को स्थापित करने तथा स्वच्छ जलाशयों में लवणीय जल के सम्मिश्रण को रोकने व स्वच्छजल के रिचार्ज संबंधी गतिविधियों के दौरान जोकि वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित हो जिसमें ई.आई.ए. भी शामिल है तथा जिसे राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा तैयार किया गया हो।

(xi) अ. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) को एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थान की मदद से उन तटीय विस्तारों के लिए एक अध्ययन करना होगा जिसके तटीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता है और ऐसे तटीय विस्तारों को 'उच्च क्षरण क्षेत्र', 'मध्यम क्षरण क्षेत्र' तथा 'निम्न क्षरण क्षेत्र' के रूप में विभक्त करना होगा। एम.ओ.ई.एफ. को राज्य प्राधिकरणों/सरकारी विभागों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर इस प्रकार के परिवर्तनों की पहचान करनी होगी तथा एक दिए हुए समय में, इस अधिसूचना के लागू होने के दिनांक से दो वर्ष के भीतर, इस प्रकार के क्षरण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

ब. तब तक उच्च क्षरण क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की बंदरगाह से संबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स. स्थानों का यह वर्गीकरण दर्शाता है कि किनारे पर होने वाले परिवर्तनों को तटीय जोन प्रबंधन स्थानों में चित्रित किया जाएगा।

(xii) शॉपिंग एवं आवासीय भवनों, होटलों एवं मनोरंजन संबंधी गतिविधियों इत्यादि के द्वारा तटीय क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण,

- (xiii) बालू, चट्टानों एवं अन्य वस्तुओं के लिए की जा रही खनन प्रक्रिया, निम्न को छोड़कर,—
अ. ऐसे पोशक तत्वों का खनन जोकि सी.आर.जेड. क्षेत्र के अलावा कहीं भी उपलब्ध नहीं है,
ब. तेल एवं प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण एवं संदोहन,
- (xiv) (क) एच.टी.एल. के अंतर्गत 200 मीटर तक के क्षेत्र में भू-गर्भीय जल का निष्कर्षण एवं इससे संबंधित प्रणालियों के व्यवस्थापन से संबंधित गतिविधियां; परन्तु यह गतिविधि उस क्षेत्र में की जा सकती है जहां स्थानीय समुदाय के लोग निवास करते हैं।
(ख) इसके अतिरिक्त इस प्रकार की गतिविधि की अनुमति 200—500 मीटर के क्षेत्र के अंतर्गत तभी दी जा सकती है जब यह गतिविधि पेयजल, सिंचाई, कृषि एवं मत्स्य पालन के लिए मानवों द्वारा किया जा रहा हो;
इस अधिसूचना में यह भी वर्णित है कि भूगर्भीय जल का निष्कर्षण ऐसे स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां पर इसके अतिरिक्त जल का स्रोत उपलब्ध न हो तथा यह गतिविधि मानवीय तरीके से, समुद्र, खाड़ी एवं एण्च्यूरी के संबंध में एच.टी.एल. से 50 मीटर से 200 मीटर क्षेत्र के अंतर्गत, पेयजल एवं अन्य घरेलू उपयोग हेतु सामान्य कुएं एवं हैण्डपम्पों से किया जा रहा हो। नदी, झील एवं बैकवाटर के संदर्भ में यह क्षेत्र 200 मीटर या सी.आर.जेड. या ऐसा कोई भी क्षेत्र जो एच.टी.एल. से कम दूरी के अंतर्गत आता हो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधि को प्रतिबंधित कर देना चाहिए जैसा कि आवश्यक हो उन क्षेत्रों में जहाँ समुद्र जल का रिसाव या बहाव हो और जो राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन के द्वारा संबंधित प्राधिकरण द्वारा लगाया जा सकता है;
- (xv) सी.आर.जेड.—I के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में की जाने वाली निर्माण संबंधी गतिविधियां, परन्तु इस अधिसूचना में पैरा 8 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार यह गतिविधि ऐसे क्षेत्रों में नहीं की जा सकती;
- (xvi) एल.टी.एल. एवं एच.टी.एल. के अंतर्गत आने वाली निर्माणात्मक गतिविधियां, परन्तु कुछ गतिविधियां हैं जिन्हें इन क्षेत्रों में किया जा सकता है जैसे समुद्र में उपचारित उत्प्रवाह एवं वाहित जल का निस्तारण, शीतलन हेतु समुद्रीजल का प्रयोग एवं इस अधिसूचना में वर्णित गतिविधियां जैसे तेल, गैस एवं अन्य पाइपलाइनों को बिछाने संबंधी आवश्यक गतिविधि।
- (xvii) सौन्दर्यीकरण या अन्य उद्देश्यों के लिए बलुई टीलों, पहाड़ियों, प्राकृतिक भू-दृश्यों में परिवर्तन करने संबंधी गतिविधियां, अधिसूचना में वर्णित गतिविधियां इस श्रेणी में नहीं आती हैं।

4. सी.आर.जेड. क्षेत्र में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का नियंत्रण — अनुमति प्राप्त गतिविधियों का नियंत्रण निम्न पर से होगा — सभी प्रकार की गतिविधियों, केवल पैराग्राफ 3 में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर, का नियंत्रण निम्न प्रकार से होगा,—

(i) अ. ऐसी गतिविधियों, जिनके लिए वाटरफ्रंट या फोरशोर सुविधाओं की आवश्यकता होती है, को सुचारु रूप से चलाने के लिए अनुमति दी जाएगी ।

ब. ऐसी परियोजनाएं जोकि इस अधिसूचना में सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 आदेश संख्या 1533(ई), दिनांक 14.09.2006 की आवश्यकता है तो इन परियोजनाओं को अनुमति तभी दी जाएगी जब राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (सी.जेड.एम.ए.) की ओर से इसकी सिफारिश की गई है ।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से निम्न गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना होगा, जैसे,—

अ. परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा संबंधी मामलों से संबंधित निर्माणात्मक गतिविधियां जिसके लिए फोरशोर सुविधाओं की आवश्यकता है जैसे स्लिपवे, जेट्टी, जलमंच, इत्यादि। रक्षा परियोजनाओं के क्रियात्मक अवयवों को छोड़कर। ऐसी परियोजनाओं के लिए एक अलग प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसे मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए। आवासीय भवन, कार्यालयी भवन, अस्पताल, वर्कशॉप इत्यादि इन क्रियात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है इसलिए इन गतिविधियों को सी.आर.जेड. क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए।

ब. निर्माण या संचालन के लिए प्राप्त हुए अनापत्ति प्रमाण की अधिकतम समय सीमा 5 वर्ष होनी चाहिए;

स. बंदरगाह एवं हार्बर, जेट्टी, जलमंच, घाट, स्लिपवे, इत्यादि का निर्माण एवं संचालन;

द. ब्रेकवाटर, ग्राउंस, क्षरण संबंधी प्रक्रिया को रोकने हेतु प्रणालियों का निर्माण एवं संचालन;

य. लाइटहाउस का निर्माण एवं संचालन;

र. कन्वेयिंग प्रणाली, पाइपलाइन एवं ट्रांसमिशन लाइन की व्यवस्था संबंधी गतिविधियां;

ल. तेल एवं प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण तथा इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां एवं सुविधाएं आदि;

(iii) ऐसी गतिविधियां जिसके लिए फोरशोर सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे कच्चे माल का

परिवहन, शीतलन हेतु जल का उपयोग एवं उपचारित वाहित मल/थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाला शीतलन जल;

- (iv) इस अधिसूचना के पैराग्राफ 8 में वर्णित तटीय विनियमन जोन में लागू की जाने वाली आवासीय योजनायें;
- (v) कम पाए जाने वाले पोषक तत्वों का खनन;
- (vi) एस.ई.जेड. में वर्णित विशिष्ट गतिविधियों/सुविधाओं के एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार द्वारा एक बार अनुमति प्राप्त करनी होगी, जोकि एस.ई.जेड. के मास्टर प्लान पर आधारित हो, सी.आर. जेड. में स्थित परियोजनाओं व इससे जुड़ी सूचनाएं जो किसी उद्देश्य के लिए जरूरी हो सकती है, को विशेष रूप से वितरित करना होगा;
- (vii) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति उत्पादन करने, डिसेलिनेशन संयंत्र एवं मौसमीय रडार जैसी सुविधाएं
- (viii) कुछ भवनों की मरम्मत एवं निर्माण (अ) पुरातात्विक या ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण (ब) धरोहर एवं सार्वजनिक उपयोग वाले भवन।
- (ix) सार्वजनिक उपयोग वाले भवन के अंतर्गत आने वाले भवनों में धार्मिक स्थल, शैक्षणिक भवन, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी भवन शामिल है।
- (x) सभी प्रकार के निर्माणात्मक एवं शहरी परियोजनाओं, जोकि 20,000 वर्ग मीटर के विस्तार से अधिक हों, के लिए ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुसार अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। 20,000 वर्ग मीटर के विस्तार से कम वाले परियोजनाओं को तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (सी. जेड.एम.ए.) से प्राप्त संस्तुति के बाद संबंधित नियोजन प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

4.2 अनुमति प्राप्त गतिविधियों को अनापत्ति प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया:—इस अधिसूचना में वर्णित सभी परियोजनाओं को निम्न प्रक्रिया के अनुसार अनापत्ति लेनी चाहिए:—

(i) परियोजना प्राधिकरण को अनापत्ति प्राप्त करने के लिए, संबंधित सी.जेड.एम.ए. से सी.आर. जेड. अधिसूचना के अनुसार पूर्व में ही निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए:—

अ. फॉर्म संख्या— 1 (अधिसूचना में वर्णित संलग्नक— IV)

ब. त्वरित ई.आई.ए. रिपोर्ट जिसमें समुद्री व स्थलीय ई.आई.ए. भी सम्मिलित हो। बंदरगाह एवं ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए, जिसमें फोरशोर सुविधाओं की आवश्यकता होती है के लिए विस्तृत ई.आई.ए. रिपोर्ट। यह रिपोर्ट एम.ओ.ई.एफ. द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होने चाहिए।

स. आपदा प्रबंधन रिपोर्ट एवं जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट

द. सी.आर.जेड. मैप या नक्शा जिसमें प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा एच.टी.एल. एवं एल.टी.एल. का स्पष्ट निर्धारण हो (1:4000 स्केल)

य. परियोजना का लेआउट जोकि उपरोक्त वर्णित मैप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो।

र. सी.आर.जेड. नक्शे में परियोजना स्थल का 7 किमी. व्यास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस नक्शों में सी.आर.जेड.—I, II, III एवं IV क्षेत्रों को अवश्य चिह्नित किया जाना चाहिए।

ल. परियोजना के लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण परिषद/समिति की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसमें उत्प्रवाह, ठोस अपशिष्ट, वहित मल इत्यादि के निस्तारण से संबंधित जानकारीयां मौजूद हों।

(ii) सी.जेड.एम.ए. को, सी.आर.जेड. एवं सी.जेड.एम.पी. अधिसूचना में लिखित निर्देशों के अनुसार ही उपरोक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहिए तथा उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के अंदर ही उन्हें अपनी संस्तुतियां निम्न प्राधिरिणों को देना होगा:—

अ. यदि परियोजना, ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत आता है तो एस.ई.ए.सी. या ई.ए.सी. को।

ब. यदि परियोजना, ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत आता है तो एम.ओ.ई.एफ. या राज्य सरकार को।

(iii) एम.ओ.ई.एफ. या राज्य सरकार को संबंधित सी.जेड.एम.ए. से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर 60 दिनों के भीतर इन परियोजनाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है या नहीं इस पर विचार करना होगा।

(iv) परियोजना की समयसीमा—

सी.आर.जेड.अधिसूचना के अंतर्गत परियोजनाओं को प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की अंतिम समय सीमा, प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष की होनी चाहिए।

(v) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद का अनुश्रवण—

अ. यदि परियोजना प्रबंधक को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण में निर्दिष्ट शर्तों एवं परिस्थितियों के अनुसार एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को, संबंधित प्राधिकरण के समक्ष, हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रत्येक वर्ष 1 जून एवं 1 दिसम्बर को प्रस्तुत करना होगा।

ब. परियोजना प्रबंधकों द्वारा जमा किए गए रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में होंगे।

स. इन दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित विनियामक प्राधिकरण को आवेदन करने पर किसी भी व्यक्ति को दी जाएंगी ।

द. ऐसी नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित होगी ।

(vi) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता—

अ. सी.जेड.एम.ए. की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सी.जेड.एम.ए. का यह उत्तरदायित्व है कि वह इसके लिए एक वेबसाइट का निर्माण करे और इस पर सी.जेड.एम.पी., उपारित किए एजेण्डे को, बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट, लिए गए निर्णय, अनापत्ति से संबंधित पत्र, उल्लंघन संबंधी मामले, की गई कार्यवाही, न्यायालय में चल रहे केसों इत्यादि को पोस्ट करे।

5. तटीय जोन प्रबंधन योजना (इसके पश्चात् सी.जेड.एम.पी.के नाम से उल्लिखित) तैयार करना :

- (i) पर्यावरण और वन मंत्रालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्र स्तरीय वैज्ञानिक संस्थान, जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेन्ट (एन.आई.एस.सी.जेड.एम.) भी शामिल हो, संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों व विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके सी.जेड.एम.पी. तैयार कराए। सी.जेड.एम.पी. तैयार करने में एम.ओ.ई.एफ. को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- (ii) देश के तटीय विस्तार के लिए जोखिम रेखा का मापन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए। जोखिम रेखा के निर्धारण के दौरान ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि एवं तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- (iii) ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण अगले पचास और सौ सालों में बाढ़ की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से तटीय विस्तार की कन्टूर मैपिंग की जाएगी, जोकि एच.टी.एल. से 0.5 मीटर से लेकर 7 किमी. के मध्य होगी। तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं से संबंधित रेखा का निर्धारण, पुराने आंकड़ों को आधार मानकर, पूर्व के सैटेलाइट चित्रों की तुलना वर्तमान के सैटेलाइट चित्रों से करके किया जाएगा।
- (iv) वृहद स्तरीय भू-उपयोग नियोजन हेतु, जोखिम रेखा निर्धारण से संबंधित मैपिंग के लिए 1:25,000 स्केल तथा स्थानीय स्तर की मैपिंग के लिए 1:10,000 स्केल का प्रयोग किया जाएगा ।

- (v) तटीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस अधिसूचना के लागू होने से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना के संलग्नक- I में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सी.आर.जेड. क्षेत्रों की पहचान कर एवं उसका वर्गीकरण कर 1:25,000 स्केल मैप सी.जेड.एम.पी. तैयार करेगी।
- (vi) तटीय क्षेत्रों की भूमि उपयोग योजना तैयार करते समय जोखिम रेखा को ध्यान में रखा जाएगा।
- (vii) सी जेड एम पी का प्रारूप संबंधित सी जेड एम ए को भेजा जाएगा जो इसका बड़े स्तर पर प्रचार करेंगे और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सी जेड एम पी प्रारूप के बारे में स्टैकहोल्डरों से टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे।
- (viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र छः महीने की अवधि के भीतर अंतिम तटीय जोन प्रबंधन योजना तैयार करेंगे और पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- (ix) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अंतिम रूप से तैयार सी जेड एम पी की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के अंदर सी जेड एम पी पर विचार करेगी और उसका अनुमोदन करेगी।
- (x) ऐसी अनुमोदित योजनाओं के कार्य ढांचे के अंतर्गत इस अधिसूचना में सूचीबद्ध सभी विकास और कार्यकलापों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या संबंधित सी जेड एम ए, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनियमन किया जाएगा।
- (xi) संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्राप्त अनुरोध के आधार पर सी जेड एम पी में इसे अंतिम रूप दिए जाने की तिथि से पांच वर्षों के बाद संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) जब तक सी.आर.जेड. 2010 के अनुरूप नए सी.जेड.एम.पी. को अनुमति नहीं मिल जाती तब तक अनुमति प्राप्त तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के तहत सी.जेड.एम.पी. का अनुपालन किया जाएगा।

6. अधिसूचना का क्रियान्वयन—

- (i) तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत उल्लंघन,—
अ. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सी.जेड.एम.ए. को सी.आर.जेड. अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत हुए उल्लंघनों को अधिसूचना के जारी होने से 3 महीने के अंदर ही पहचानना होगा तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही इस

अधिसूचना के लागू होने से 6 महीने के अंदर ही इसके विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने के लिए।

ब. सी.आर.जेड. अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत हुए ऐसे उल्लंघनों, जिनकी पहचान हो चुकी है, के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने का उत्तरदायित्व राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों का है।

जिसका अनुपालन इस अधिसूचना के लागू होने से 6 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए;

स. सी.आर.जेड. अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत हुए समस्त उल्लंघनों व इसके विरुद्ध की गई कार्यवाहियों को संबंधित सी.जेड.एम.ए. एवं एम.ओ.ई.एफ. द्वारा तटीय जोन प्रबंधन के लिए विशेष रूप से बनाए गए वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए;

(ii) सी.आर.जेड., अधिसूचना, 2010 का प्रवर्तन—

अ. सी.आर.जेड. अधिसूचना, 2010 के उचित क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एम.ओ.ई.एफ., दिल्ली, संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के पर्यावरण विभाग या राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश में सी.आर.जेड. के क्षेत्र में कार्यरत विभागों/एजेन्सियों की होनी चाहिए;

ब. सी.आर.जेड. के उचित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेन्ट अथॉरिटी (एन.सी.जेड.एम.ए.) एवं 13 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सी.जेड.एम.ए. को रिट पिटिशन संख्या 1993 का 664 के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नोटिस भेज सकती है;

स. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित एन.सी.जेड.एम.ए. के अलावा भी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सी.जेड.एम.ए. को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि वे सी.आर.जेड. अधिसूचना, 2010 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कर सकें।

द. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार एन.सी.जेड.एम.ए. एवं सी.जेड.एम.ए. को सी.आर.जेड. अधिसूचना, 2010 के अंतर्गत होने वाले उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का पर्याप्त शक्ति प्राप्त होगी;

य. 6.2 (अ) एवं (घ) में वर्णित एजेन्सियां/प्राधिकरणों, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत लिखित अधिकारों एवं कार्यों के साथ-साथ किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या कोई प्राधिकरण एवं ऐसे किसी भी व्यक्ति को दिशा-निर्देश देगी तथा ये सभी व्यक्ति, अधिकारी इत्यादि उसके आदेश का पालन करेंगे;

र. ऐसी स्थिति में जब एम.ओ.ई.एफ., एन.सी.जेड.एम.ए. एवं राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सी.जेड.एम.ए. ऐसा मानते हैं कि तटीय पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान होने की संभावना है,

उस दशा में प्रस्तावित निर्देशों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसरन दिया जाए, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके अवसर न देते हुए निर्देश जारी किए जा सकते हैं:

7. सी.आर.जेड. क्षेत्र का वर्गीकरण—तटीय क्षेत्रों एवं समुद्री जल के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य से, सी.आर.जेड. क्षेत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं:—

(i) सी.आर.जेड.—I,—

अ. ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एवं ऐसी भू-आकारिकी विशेषताएं जोकि तटों की अखण्डता को बनाए रखने में आवश्यक है इसके अंतर्गत आती हैं। सी.आर.जेड.— 1 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं,—

क. मैन्ग्रूव क्षेत्र। यदि मैन्ग्रूव क्षेत्र का विस्तार 1000 वर्ग मी. से अधिक है तो 50 मीटर के क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए;

ख. प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति तथा इससे जुड़ी जैवविविधता;

ग. बलुई टीले;

घ. तटीय नमभूमि (मडफ्लैट) जहां जैविक विविधता हो;

च. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत सूचीबद्ध राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री उद्यान, वन्यजीव विहार, संरक्षित वन, वन्यजीव पर्यावास एवं अन्य संरक्षित क्षेत्र;

छ. नमकीन दलदल;

ज. कछुआ प्रजनन स्थल;

झ. हॉर्स शू केकड़े का पर्यावास;

ट. समुद्री घास का मैदान;

ठ. पक्षियों के प्रजनन का स्थान;

ड. पुरातात्विक महत्ता वाला क्षेत्र/संरचना तथा धरोहर स्थल;

ब. ऐसे क्षेत्र जो निम्न ज्वार रेखा एवं उच्च ज्वार रेखा के मध्य स्थित हैं; और

स. ऐसे क्षेत्र जो समुद्री जल स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप जलमग्न हो सकता है;

(ii) सी.आर.जेड. - II,—

ऐसे क्षेत्र जो तटीय रेखा के एकदम निकट विकसित या स्थित हों।

स्पष्टीकरण : अभिव्याक्त के प्रयोजनार्थ क्षेत्रों को 'विकसित क्षेत्र' कहते हैं जो यह क्षेत्र नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह क्षेत्र कानूनन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि पहले से निर्मित हो चुका है तथा जहां उचित जलनिकास प्रणाली एवं सड़कें एवं अन्य आधारभूत ढांचे जैसे जलापूर्ति एवं वाहितमल निकास प्रणाली मौजूद है।

(iii) सी.आर.जेड.— III,—

ऐसे क्षेत्र जोकि अभी तक अव्यवस्थित नहीं है तथा जिन्हें श्रेणी— I एवं II में शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत वह तटीय क्षेत्र आता है जो ग्रामीण इलाकों (विकसित एवं अविकसित) में स्थित है और ऐसे क्षेत्र जो नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह क्षेत्र कानूनन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि पहले से निर्मित न हुआ हो।

(iv) सी.आर.जेड.— IV,—

अ. समुद्र की ओर उच्च ज्वार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी का जलीय क्षेत्र;

ब. ज्वार से प्रभावित जलाशयों के आसपास का जलीय क्षेत्र जोकि समुद्र की ओर स्थित जलाशय के मुख से ज्वार से प्रभावित क्षेत्र के मध्य आता है। इस दूरी का निर्धारण वर्ष के शुष्क काल में लवणीयता की मात्रा को 5 पार्ट्स पर थाउसेण्ड (पी.पी.टी.) को आधार मानकर किया जाना चाहिए।

(v) क्षेत्र जिनका विशेष ध्यान देना आवश्यक है,—

अ. महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध ऐसे सी.आर.जेड. क्षेत्र जो ग्रेटर मुम्बई एवं नवी मुम्बई के नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है;

ब. केरल राज्य का कोच्चिन क्षेत्र जिसमें बैकवाटर एवं बैकवाटर द्वीप स्थित है;

स. पश्चिम बंगाल का हुगली क्षेत्र;

द. गोवा का सी.आर.जेड. क्षेत्र।

गतिविधियों के संचालन से संबंधित विधियाँ—

(1) ऐसी परियोजनाओं जिन्हें लागू करना सी.आर.जेड. में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, के लिए अनुमति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं।

(ii) सी.आर.जेड. की विभिन्न श्रेणियों में होने वाले विकासात्मक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियाँ का नियंत्रण राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के संबंधित प्राधिकरण द्वारा निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए:-

1. सी.आर.जेड.- I,-

(i) सी.आर.जेड.- I में किसी प्रकार की नई निर्माण प्रक्रिया की अनुमति नहीं देनी चाहिए, निम्न को छोड़कर,-

अ. परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजना;

ब. पाइपलाइन, संप्रेशण प्रणाली जिसमें ट्रांसमिशन लाइन भी सम्मिलित हैं;

स. सी.आर.जेड.- I में अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ के लिए आवश्यक सुविधाएँ;

द. भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवातों एवं तूफानों की गति तथा पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए स्थापित मौसमीय राडार;

य. एल.टी.एल. एवं एच.टी.एल. के मध्य, ज्वारीय प्रवाह को नुकसान पहुँचाए बिना,

अवस्तंभ या खम्भों पर ट्रांसहार्बर समुद्री मार्ग या सड़क का निर्माण;

र. नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास एवं इससे जुड़ी गतिविधियाँ संबंधी गतिविधियाँ;

(ii) एल.टी.एल. एवं एच.टी.एल. के मध्य के मध्य का ऐसे क्षेत्र, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील न हो तथा महत्वपूर्ण हो, में निम्न गतिविधियों को करने की अनुमति है,-

अ. प्राकृतिक गैस का उत्खनन एवं निष्कर्षण;

ब. गतिविधियाँ जोकि पैराग्राफ (2) में स्पष्ट की गई हैं;

स. संबंधित सी.जेड.एम.ए. से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संरक्षित बायोस्फियर में निवास करने वाले पारंपरिक समुदाय की आवश्यकता हेतु चिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क, जल, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वाहित मल के निकास की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण एवं विकास; यदि ऐसे क्षेत्र खतरनाक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए;

द. समुद्री जल का वाष्पीकरण करके नमक बनाने की विधि;

य. डिसेलिनेशन संयंत्र;

र. पूर्वनिर्धारित बंदरगाहों पर खाद्य तैल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का भण्डारण;

ल. ज्वारीय प्रवाह को नुकसान पहुंचाए बिना, अवस्तंभ या खम्भों पर ट्रांसहाबर्स समुद्री मार्ग या सड़क का निर्माण;

II. सी.आर.जेड.— II,—

(i) पहले से निर्मित सड़कों के भूमि की ओर (या ऐसी सड़के जो प्रमाणित किए गए सी.जेड.एम.पी.में वर्णित क्षेत्र में आते हों) या किसी प्राधिकरण से संबंधित भवनों के भूमि की ओर या खतरे की रेखा के ओर की भूमि पर, यदि वहां पहले से कोई भी प्राधिकृत संरचनाएं न हो, भवनों के निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ii) वे भवन जिन्हें, पहले से निर्मित या प्रस्तावित सड़कों/पहले से निर्मित किसी प्राधिकरण से संबंधित भवनों के भूमि की ओर, बनाए जाने की अनुमति प्राप्त है, स्थानीय शहरी या देश के नियोजन, जिसके अंतर्गत फ्लोर स्पेस इण्डेक्स/फ्लोर एरिया रेशियो से संबंधित पूर्व स्थित (पूर्व स्थित अर्थात्—19.2.1991) को स्थित नियम भी शामिल है, के अध्वधीन होंगे।

बशर्ते कि समुद्र की ओर पहले से निर्मित सड़क पर बने नए सड़को (ऐसी सड़के जो प्रमाणित किए गए सी.जेड.एम.पी. में प्रस्तावित हों) की ओर की भूमि पर किसी भी प्रकार के भवनों के निर्माण की प्रक्रिया को अनुमति नहीं दी जाएगी :

बशर्ते यह भी कि प्रमाणित किए गए सी.जेड.एम.पी. में निर्मित या प्रस्तावित सड़कों के साथ-साथ पूर्व में निर्मित सड़क/प्राधिकृत संरचनाओं को आधार मानकर, निर्माण पर लगे उपरोक्त प्रतिबंध राज्य शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। परन्तु इस संदर्भ में बत यह है कि यह सभी गतिविधियां 19.02.1991 के पूर्व ही कर ली गई हों तथा इस गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों ने 19 फरवरी 1991 से पहले समस्त प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर लिया हो; इन सभी मामलों में केस दर केस के आधार एम.ओ.ई.एफ. से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा;

(ii) प्राधिकृत संरचनाओं के पुर्ननिर्माण की प्रक्रिया की अनुमति, पूर्वनिर्धारित

फ्लोर स्पेस इण्डेक्स/फ्लोर एरिया रेषियो नियम के अनुसार ही बिना किसी बदलाव के, दी जानी चाहिए;

(iii) नए भवनों का निर्माण एवं उसकी संरचना आसपास के भूआकारिकी एवं स्थानीय अवसंरचना की तरह होनी चाहिए;

(iv) अधिसूचना के संलग्नक-II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं भण्डारण के साथ-साथ तरल पैरा 2 (ii) में दिए गए नियम के अनुसार प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;

(v) डिसेलिनेशन संयंत्र एवं इससे जुड़ी अन्य सुविधाएं;

(vi) पूर्वनिर्धारित बंदरगाहों पर खाद्य तैल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का भण्डारण;

(vii) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति उत्पादन करने व इससे जुड़ी सुविधाएं;

III. सी.आर.जेड.- III.-

अ. एच.टी.एल. से 200 मीटर तक भूमि की ओर के क्षेत्र को नो डेवेलपमेन्ट जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(i) पूर्वनिर्धारित बंदरगाह एवं स्पेशल इकोनोमिक जोन में आने वाले क्षेत्र नो डेवेलपमेन्ट जोन के अंतर्गत नहीं आयेंगे;

(ii) इस जोन के अंतर्गत पूर्व में निर्मित प्राधिकृत संरचनाओं में पूर्वनिर्धारित फ्लोर स्पेस इण्डेक्स, प्लिन्थ एरिया एवं घनत्व में बिना परिवर्तन किए, उनकी मरम्मत या पुर्ननिर्माण तथा इस अधिसूचना में लिखित आवश्यक गतिविधियों से संबंधित सुविधाओं के निर्माण को छोड़कर, किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति प्राप्त नहीं होनी चाहिए;

(iii) हालांकि इस जोन में निम्न गतिविधियों को सांचलित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है: कृषि, शाक-भाजी उत्पादन, बगीचे की व्यवस्था, चारागाह, पार्क, खेलने का मैदान, वन;

(iv) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं;

(v) कम पाए जाने वाले पोशक तत्वों का खनन;

(vi) समुद्री जल से नमक बनाना;

- (vii) अधिसूचना के संलग्नक-II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं भण्डारण;
- (viii) पैरा 2 (ii) में दिए गए नियम के अनुसार प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;
- (ix) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति उत्पादन करने की सुविधाएं;
- (x) डिसेलिनेशन संयंत्र एवं इससे जुड़ी सुविधाएं;
- (xi) मौसमीय राडार की स्थापना;
- (xii) संबंधित सी.जेड.एम.ए. से अनुमति प्राप्त स्थानीय समुदाय की आवश्यकता हेतु चिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क, जेट्टी, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वाहित मल के निकास की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण एवं विकास की अनुमति दी जा सकती है;
- (xiii) घरेलू वाहित मल, उपचार एवं निस्तारण के लिए बनाए जाने वाली इकाइयों या संबंधित निकायों हेतु प्रदूषण नियंत्रण परिषद्/समिति की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए;
- (xiv) स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे मछलियों को सुखाने के लिए प्रांगण, निलामे के लिए एक हॉल, पारंपरिक नौका निर्माण संबंधी प्रांगण, बर्फ तोड़ने की इकाई, मछलियों के उपचार से संबंधित सुविधाएं इत्यादि।

ब. 200 मीटर से 500 मीटर तक का क्षेत्र:—

- (i) एच.टी.एल. के 200 मीटर से 500 मीटर तक का रिक्त क्षेत्र सी.आर.जेड.—III कहलाता है जिसके विकास के लिए एम.ओ.ई.एफ. से पूर्व में ही अनुमति लेनी होगी। इस क्षेत्र में, अधिसूचना में निहित संलग्नक III के दिशा-निर्देश के आधार पर पर्यटकों/आगन्तुकों हेतु होटल/समुद्र तटीय रिसॉर्ट इत्यादि के विकास की ही अनुमति होगी।
- (ii) अधिसूचना के संलग्नक-II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं भण्डारण;
- (iii) पैरा 2 (ii) में दिए गए नियम के अनुसार प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;

(iv) पूर्वनिर्धारित बंदरगाहों पर खाद्य तैल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का भण्डारण;

(v) डिसेलिनेशन संयंत्र एवं इससे जुड़ी सुविधाएं;

(vi) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति उत्पादन करने व इससे जुड़ी सुविधाएं;

(vii) आवासीय इकाईयों की मरम्मत एवं निर्माण की गतिविधि की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए शर्त यह है कि यह इकाईयां मछुआरा समुदायों एवं गोथान्स के पारंपरिक अधिकारों एवं सांस्कृतिक प्रयोगों के अंतर्गत आती हों। इस प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए शर्त यह है कि आवासीय इकाईयों की संख्या पूर्व में निर्मित या पहले से मौजूद इकाईयों से दोगुने से अधिक न हो; इन्हें बनाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल प्लॉट के क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत से अधिक न हो; ढांचे की अधिकतम उंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ढांचा दो मंजिल (ग्राउण्ड+प्रथम मंजिल) से ज्यादा नहीं होना चाहिए;

(viii) अधिसूचना के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों, जिसमें इन गतिविधियों से संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं, के लिए निर्माण संबंधी कार्य की अनुमति है;

(ix) राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा नियुक्त प्राधिकरण वर्षा से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों, सामुदायिक शौचालयों, जलापूर्ति व्यवस्था, वाहितमल निस्तारण संबंधी व्यवस्था, सड़क एवं पुलों के निर्माण की आज्ञा दे सकता है। यह प्राधिकरण, यदि निर्माण हेतु अन्य स्थान उपलब्ध नहीं है तो सी.आर.जेड. के अंतर्गत आने वाले अधिकतर पंचायतों में निवास करने वाले स्थानीय लोगों के लिए स्कूल एवं चिकित्सालय के निर्माण की भी अनुमति प्रदान कर सकता है;

(x) इस क्षेत्र में पहले से मौजूद प्राधिकृत भवनों की मरम्मत/निर्माण की भी अनुमति प्राप्त है जोकि निर्देश संख्या (vii), (viii) एवं (ix) के आधार पर ही संभव है;

(xi) स्पेशल इकोनोमिक जोन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पहले से ही निर्धारित किए गए

स्पेशल इकोनोमिक जोन (एस.ई.जेड.) के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा अन्य सेवा उद्योगों के क्षेत्र में प्रदूषण रहित उद्योगों, डिसेलिनेशन संयंत्रों, समुद्र तटीय

रिसॉर्टों एवं इससे संबंधित आरामदायक सुविधाओं के निर्माण की अनुमति, स्पेशल इकोनोमिक जोन प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त मास्टर प्लान के आधार पर दी जा सकती है;

(xii) नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास एवं इससे जुड़ी निर्माण संबंधी गतिविधियां;

IV. सी.आर.जेड.— IV में,—

अ. अनुपचारित वाहितमल, उत्प्रावह या ठोस अपशिष्ट को नहीं डालना या फेंकना चाहिए। वाहितमल के उचित उपचार एवं निस्तारण के लिए शहर को, इस अधिसूचना के लागू होने से ठीक एक वर्ष के अंदर ही अंदर, एक कार्यकारी योजना का विकास करना चाहिए तथा इसके पश्चात् दो वर्षों के अंदर इसे लागू भी करना चाहिए।

ब. स्थानीय समुदाय मछली पकड़ने व इससे संबंधित गतिविधियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है।

स. स्थानीय समुदायों द्वारा शुरू किए गए मत्स्य आखेट और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं होगी।

V. ऐसा क्षेत्र जिसपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है,—

1. ऐसे सी.आर.जेड. क्षेत्र जो ग्रेटर मुम्बई एवं नवी मुम्बई के नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है;

(i) अनुपचारित उत्प्रावहों, ठोस अपशिष्टों के निस्तारण के कारण होने वाले मैन्ग्रूव वनों के क्षरण, झीलों एवं तटीय जलों के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तथा गरीबों को बेहतर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने मुम्बई एवं नवी मुम्बई के सी.आर.जेड. क्षेत्रों के लिए विशेष नियमों को तैयार किया है। मुम्बई एवं नवी मुम्बई के सी.आर.जेड. क्षेत्रों में होने वाले समस्त विकासात्मक गतिविधियों का नियंत्रण निम्न प्रकार से होना चाहिए—

(ii) ग्रेटर मुम्बई के सी आर जेड क्षेत्र में सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यकलाप निम्नलिखित दंग से विनियमित किए जाएंगे :—

अ. अधिसूचना के अनुच्छेद 7 के उप-अनुच्छेद (i) में बताए गए अनुसार सी आर जेड—। में केवल निम्नलिखित कार्यकलाप ही शुरू किए जा सकते हैं—

अ. मुम्बई एवं नवी मुम्बई के विकास संबंधी योजना में अवस्तंभ या खम्भों पर अनुमति प्राप्त सड़कों एवं मिसिंग लिंक का निर्माण किया जाना चाहिए। निर्माण के समय यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे समुद्री ज्वारीय प्रवाह को कोई नुकसान नहीं होगा।

ब. यदि निर्माण के दौरान मैन्ग्रूव वनों का क्षरण होता है तो इन्हें दोबारा लगाना चाहिए।

स. अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल के भीतर;

(1) सभी मैंग्रोव क्षेत्रों का मापन किया जाएगा और सुरक्षित वनों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा पहचान किए गए मैंग्रोव क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा और संरक्षण उपाय शुरू किए जाएंगे।

(2) सी आर जेड क्षेत्र के बाहर ठोस अपशिष्ट स्थलों की पहचान की जाएगी और उसके पश्चात एक साल के भीतर मौजूदा कन्वेंशन ठोस अपशिष्ट स्थलों को सी आर जेड क्षेत्र के बाहर ले जाया जाएगा।

(3) जोखिम रेखा समुद्र की ओर स्थित निवास स्थलों और ढांचों की सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना शुरू की जाएगी।

(iii) सी आर जेड - II क्षेत्रों में-

अ. नगर और शहर योजना विनियम जैसे कि तारीख 19.2.1991 की अधिसूचना जारी होने की तारीख को थे, में दिए गए मानकों के अनुसार विकास और जीर्णोद्धार निरंतर जारी रहेगा, जब तक कि त्वरित अधिसूचना में इसे अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

ब. मलिन बस्ती पुनर्वास स्कीमें : ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में बड़ी संख्या में मलिन बस्तियां हैं जिनमें लाखों परिवार रहते हैं। इन मलिन बस्तियों की जीवन दशाएं बहुत खराब हैं और नागरिक अभिकरण यहां पेयजल, बिजली, सड़कों, नालियों आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ है, क्योंकि मलिन बस्तियां अनियोजित और घनी बसी हैं। इसके अतिरिक्त बचाव राहत और खाली करने की दृष्टि से होने वाली परेशानियों के मददेनजर तटीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों को चक्रवात, तूफान अथवा सुनामी का बहुत खतरा है। इसलिए मलिन बस्ती के निवासियों को सुरक्षित और उपयुक्त निवास स्थान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सीधे या अपनी सहायक एजेंसियों जैसे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम एच ए डी ए), शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड (एस पी पी एल), मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम एम आर डी ए) आदि के माध्यम से मलिन बस्ती पुनर्विकास स्कीमें कार्यान्वित कर सकती है। बशर्ते कि :-

1. ऐसी पुनर्विकास स्कीमें यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें राज्य सरकारों या उनके सहायक निकायों का अंश 51% से कम न हो। सीधे या संयुक्त रूप से या सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी अथवा ऐसे समान मॉड्यूल से शुरू की जाएंगी।
2. ऐसी जीर्णोद्धार स्कीमों के लिए फ्लोर स्पेस इन्डेक्स या फ्लोर एरिया अनुपात सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को दी गई मंजूरी की तारीख को मौजूद नगर और शहर योजना विनियम के अनुसार होगा।
3. शर्त राज्य सरकार सहित यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी रूप से विनियमित सभी किरायेदारों को अपने स्थान पर अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए मानकों के अनुसार मकान उपलब्ध कराए गए हैं, उनके साथ पुनर्विकास शुरू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

स. **जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवनों का पुनर्निर्माण :** ग्रेटर मुंबई में भी सी आर जेड क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवन हैं। अपनी स्थिति के कारण ये ढांचे अत्यंत असुरक्षित और आपदा की संभावना वाले हैं। इसलिए इन अभिनिर्धारित भवनों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण अत्यंत आवश्यक है। ये परियोजनाएं निम्नलिखित शर्तों और सुरक्षा उपायों के अधीन शुरू की जाएंगी।

1. ऐसी पुनर्विकास / पुनर्निर्माण परियोजनाएं इन भवनों के मालिकों या निजी डेवलपर्स को शामिल करते हुए मौजूदा विनियम के अनुसार सीधे या संयुक्त रूप से या अन्य समान मॉड्यूल के माध्यम से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
2. ऐसी जीर्णोद्धार स्कीमों के लिए फ्लोर स्पेस इन्डेक्स या फ्लोर एरिया अनुपात सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को दी गई मंजूरी की तारीख को मौजूद नगर और शहर योजना विनियम के अनुसार होगा।
3. उपर्युक्त शर्त (1) के माध्यम से पुनर्निर्माण शुरू करते समय परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भवनों के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण के दौरान विशिष्ट भवनों के वास्तविक किराएदारों के लिए उचित आवास सुनिश्चित किया जाएगा।

द. त्वरित अधिसूचना में कहीं भी, कुछ भी शामिल होने के बावजूद उपर्युक्त पैरा ब और स में विशिष्ट रूप से दी गई मलिन बस्तियों और जीर्ण-शीर्ण उपकर आधारित और असुरक्षित भवनों के लिए विकासात्मक कार्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उसमें बताए गए जवाबदेह और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जाएंगे, जिसमें जहां भी लागू हो, निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे :-

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई सभी जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए आर टी आई अधिनियम, 2003 की अनुप्रोद्यता।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा निष्पादन और राजकोषीय लेखा परीक्षण।

3. महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवधिक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की स्थापना करना, जिसमें स्थानीय शहरीनिकायों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न स्टेक हॉल्डरों, वास्तुविदों, शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों और नागरिक समाज के ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(य) ग्रेटर मुंबई क्षेत्र के 'ग्रीनलंग' की सुरक्षा और परिरक्षा के लिए सभी खुले स्थानों, पार्कों, उद्यानों, सी आर जेड-II के अंदर की विकास योजनाओं में निर्धारित क्रीड़ास्थलों को सी आर जेड-III, जोकि 'नो डेवलपमेंट जोन' है, के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, नागरिक सुविधाओं, मनोरंजन और खेलकूद से संबंधित कार्यों के लिए स्टेडियम, जिम्नाजियम आदि निर्माण के लिए ही 15% फ्लोर स्पेस इंडेक्स की अनुमति होगी। ऐसे खुले स्थानों के आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

(र) राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों से संबंधित आवासीय इकाइयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के बारे में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा और अनुमति दी जाएगी।

2. केरल का सी.आर.जेड.

(i) केरल के बैकवाटर में स्थित समस्त द्वीप सी.आर.जेड. अधिसूचना के अंतर्गत आने चाहिए।

(ii) बैकवाटर में मौजूद द्वीप के पास भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा से लेकर 50 मीटर तक का सी.आर.जेड. क्षेत्र होना चाहिए।

(iii) इन बैकवाट प्रायद्वीपों के एच.टी.एल. से 50 मीटर के अंतर्गत स्थित स्थानीय समुदायों के आवासीय स्थल की मरम्मत या इसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। किसर प्रकार का नवीन निर्माण इस क्षेत्र में नहीं होगा।

(iv) बैकवाटर प्रायद्वीपों की भूमि की ओर एच.टी.एल. से 50 मीटर दूरी के बाद स्थित स्थानीय समुदायों के आवासीय स्थल का निर्माण स्थानीय पंचायत की आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता।

(v) फोरशोर सुविधाएं जैसे मछली पकड़ने के लिए जेट्टी, मछली सुखाने के लिए निश्चित स्थान का निर्माण, पारंपरिक तरीके से किया जाने वाला मत्स्य प्रसंस्करण,

नौका निर्माण के लिए स्थान, नौका की मरम्मत इत्यादि कार्य इन बैकवाटर प्रायद्वीपों के 0-50 मीटर के अंदर किया जा सकता है ।

3. गोवा का सी.आर.जेड.

(i) गोवा सरकार को गोवा के समुद्र तट के आसपास के मछुआरा गांवों का सर्वेक्षण करके एक नक्शा बनाना होगा। इसके पश्चात् ही इन्हें मत्स्य पालन एवं इससे संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक अन्य प्रकार की सुविधाएं जैसे पारंपरिक तरीके से किया जाने वाले मत्स्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया संबंधी स्थान, नौका निर्माण/मरम्मत के लिए स्थान, बर्फ को संग्रह करने का स्थान, निलामी संबंधी हॉल, जेट्टी इत्यादि को उपलब्ध कराना चाहिए।

(ii) सी.आर.जेड. में स्थानीय समुदायिक संरचनाओं के निर्माण एवं मरम्मत की गतिविधि की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) ऐसे इको संवेदनशील निचले क्षेत्रों, जोकि ज्वार से प्रभावित होते हैं तथा जिन्हें खलान भूमि भी कहते हैं का नक्शा बनाना चाहिए। इस खलान भूमि के आसपास स्थित मैन्ग्रूव वनों की सुरक्षा की जानी चाहिए तथा इन क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित एक योजना का विकास भी किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(iv) खाड़ियों एवं झीलों के आसपास स्थित बलुई टीलों व तटीय विस्तारों का सर्वेक्षण कर नक्शा तैयार किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति इस क्षेत्र में नहीं दी जानी चाहिए।

(v) खाड़ियों और छोटी नदियों के किनारे के रेत के टीलों, समुद्र तटों का सर्वेक्षण और मापन किया जाएगा ।

(vi) मैट्रैम, मोरीजिम, गालगिवा और अगोंडा जैसे तटीय क्षेत्रों के कछुओं के निवास स्थान के स्थान के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा और कछुओं के निवास स्थान वाले इन स्थानों की सुरक्षा के लिए प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी ।

(vii) उप-अनुच्छेद (vi) में उल्लिखित कछुआ प्रजनन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. सुन्दरबन तथा अन्य पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सी.

आर.जेड.:

अ. समस्त सुन्दरबन जैवमंडल एवं अन्य चिह्नित पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे गुजरात का खम्बत खाड़ी एवं कच्छ का क्षेत्र, मलवन, महाराष्ट्र में वासासी-मनोरी, कर्नाटक में अचरा-रत्नागिरी, करवर एवं कुण्डापुर, केरल का वेम्बानाद, उड़ीसा का भैतरकनिका, आन्ध्र प्रदेश को कोरिन्गम, पूर्व गोदावरी एवं कश्ष्णा को अत्यंत संवेदनशील तटीय क्षेत्र (क्रिटिकली वलनरेबल कोस्टल एरिया) घोषित किया जाना चाहिए।

ब. मैन्ग्रूव के संरक्षण एवं प्रबंधन, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं जैसे चिकित्सालय, विद्यालय, वर्षा से बचने के लिए शरण स्थल, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क, जेट्टी, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वाहित मल के निकास की व्यवस्था एवं समुद्री जल स्तर में वृद्धि सक होने वाले प्रभावों, को ध्यान में रखते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर ही एक एकीकृत प्रबंधन योजना को विकास किया जाना चाहिए।

स. सुन्दरबन एवं पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों के लिए, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुसार प्राप्त विचारों एवं मतों के आधार पर एक एकीकृत प्रबंधन योजना (आई.एम.पी.) का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसको मंत्रालय द्वारा प्रमाणित करके उसे जारी कर देना चाहिए।

द. प्रमाणित किए गए आई.एम.पी. को समयानुसार लागू करना चाहिए तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा इसे लागू करने में पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए।

य. आई.एम.पी. को प्रमाणित करने तथा उसकी घोषणा करने तक, पारंपरिक तौर पर निवास करने वाले समुदाय की आवश्यकताओं हेतु चिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क, जेट्टी, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वाहित मल के निकास वर्षा से बचने के लिए शरण स्थल, की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण एवं विकास की अनुमति संबंधित सी.जेड. एम.ए. द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए।

अनुबंध—I**तटीय जोन प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश****1. अ. उच्च ज्वार रेखा का चिन्हांकन**

1. नेशनल सेन्टर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन (एन.एस.सी.एस.जेड.) की संस्तुतियों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था को उच्च ज्वार रेखा (एच.टी.एल.) और निम्न ज्वार रेखा (एल.टी.एल.) को चिन्हांकित करना होगा।
2. एच.टी.एल./एल.टी.एल. का चिन्हांकन केन्द्र सरकार द्वारा चयनित संस्थाओं द्वारा निर्मित तटीय जोन प्रबंधन (सी.जेड.एम.) मानचित्र जोकि 1:25,000 पैमाने के माप के अनुसार है, पर करना होगा।
3. स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा सी.आर.जेड. को चिन्हांकित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सी.एम.जेड. मानचित्र का निर्माण करना होगा।
4. केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता दिये गये सी.जेड.एम. मैप के अनुसार ही कैडेस्ट्रल पैमाने पर स्थानीय सी.जेड.एम. मानचित्र तैयार किये जायेंगे।

ब. सी.जेड.एम. मानचित्र का निर्माण:

5. 1:25,000 पैमाने का आधार मानचित्र सर्वे ऑफ इण्डिया (एस.ओ.आई.) से लिया जायेगा। यदि 1:25,000 पैमाने का मानचित्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आधार मानचित्र के रूप में 1:50,000 पैमाने के मानचित्र को 1:25,000 तक बड़ा करके प्रयोग किया जायेगा। इन मानचित्रों के विशिष्ट मानक निम्नांकित मानकों के अनुरूप होंगे।

ईकाई	:	7.5 मिनट x 7.5 मिनट
अंकन	:	सर्वे ऑफ इण्डिया की सीट के साख्यांकन के अनुसार
क्षैतिज	:	एवरेस्ट या डब्ल्यू.जी.एस. 84
ऊर्ध्वाधर	:	मीन सी लेवल (एम.एस.एल.)
स्थलाकृति	:	एस.ओ.आई मानचित्र की स्थलाकृति को आधुनिक सेटलाइट इमेजेनरी एरियल फोटोग्राफ्स

6. आधार मानचित्र पर चिन्हांकित उच्च जल स्तर (एच.डब्ल्यू.एल.) तथा निम्न जल स्तर (एल.डब्ल्यू.एल.) को सी.जेड.एम. मानचित्र पर हस्तांतरित किया जायेगा।
7. सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुसार एच.टी.एल./एल.टी.एल. को चिन्हांकित करने के लिए एच.डब्ल्यू.एल./एल.डब्ल्यू.एल. में उचित समायोजन हेतु फील्ड/सेटलाइट इमेजेनरी/एरियल फोटोग्राफ में तटीय भू-आकृतिकीय चिन्हों को प्रयोग किया जायेगा। ये केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

8. एच.टी.एल./एल.टी.एल. को चिन्हांकित करते समय निम्नांकित भू-आकृतिकीय विशेषताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

बलुई समुद्री तट के संदर्भ में स्थल की ओर (मानसूनी) का शिरा
पत्थर, समुद्रगत भूमि, खड़ी चट्टानें
समुद्र तटबंध/रिवीटमेन्ट/तटबंध

9. एच.टी.एल. के लिए 500 मी. और 200 मी. की रेखा को चिन्हांकित किया जायेगा।

10. एच.टी.एल. (जैसाकि सी.आर.जेड. अधिसूचना में परिभाषित है) और एल.टी.एल. को भी सी.जेड. एम. मानचित्र में भू-आकृतिकीय चिन्हों/विशेषताओं के माध्यम से ज्वार द्वारा प्रभावित होने वाले अर्न्तस्थलीय जल स्रोतों के किनारों के चारों ओर चिन्हांकित किया जायेगा।

11. सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुसार विभिन्न समुद्रतटीय क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जायेगा।

12. आंकड़ों के उप-वर्गीकरण को प्रकट करने के लिए मानक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रंग कोडों को प्रयोग किया जायेगा।

स. स्थानीय सी.जेड.एम. मानचित्र:

स्थानीय सी.जेड.एम. मानचित्र, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं के प्रयोग हेतु है।

13. अधिकशति (ग्रामीण) मानचित्र जोकि 1:3960 या इसके नजदीकी पैमाने पर होंगे, को आधार मानचित्रों के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

14. ये मानचित्र राजस्व प्राधिकरणों के पास उपलब्ध होते हैं और मानकों के अनुरूप तैयार किये जाते हैं।

15. एच.टी.एल. (जैसाकि सी.आर.जेड. अधिसूचना में परिभाषित है) और एल.टी.एल. को भी अधिकशत मानचित्र में विस्तृत भौतिक सत्यापन के आधार पर चिन्हांकित किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सी.जेड.एम. मानचित्रों के अनुसार तटीय भू-आकृतिकीय चिन्हों/विशेषताओं का प्रयोग किया जायेगा।

16. एच.टी.एल. चिन्ह के अनुसार 500 मी. और 200 मी. की सीमा रेखा का चिन्हांकन किया जायेगा।

17. एच.टी.एल. (जैसाकि सी.आर.जेड. अधिसूचना में परिभाषित है) और एल.टी.एल. को भी भू-आकृतिकीय चिन्हों/विशेषताओं के माध्यम से ज्वार द्वारा प्रभावित होने वाले अर्न्तस्थलीय जल स्रोतों के किनारों के चारों ओर चिन्हांकित किया जायेगा।

18. परिभाषाओं को सी.जेड.एम. मानचित्रों से स्थानीय सी.जेड.एम. मानचित्रों में स्थानांतरित किया जायेगा।

19. सी.जेड.एम. मानचित्र से सूचकों को लिया जायेगा।
20. सी.जेड.एम. मानचित्र में दिये गये रंग संकेतकों (कोडों) का प्रयोग किया जायेगा।
21. केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से अधिकृत मानचित्र का सत्यापन किया जायेगा। स्थानीय संस्थायें संबंधित राज्य/केन्द्रशासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशन में कार्य करेंगी।

द. जोखिम/खतरों का मापन:

II. सी.आर.जेड. क्षेत्रों का वर्गीकरण

1. सी.जेड.एम. मानचित्र को सी.आर.जेड. अधिसूचना के पैरा 5 जिसमें सी.आर.जेड. I, II, III, IV और V को चिह्नित किया गया है, के अनुसार तैयार किया जायेगा।
2. सी.जेड.एम. मानचित्र, क्षेत्र की भू-उपयोग योजना और सी.आर.जेड 1 क्षेत्रों की सूची को स्पष्ट रूप से चिह्नित करेगा। पैरा 7(I) ए और बी के तहत सूचीबद्ध सभी सी.आर.जेड. — क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित, और रंग कोड निर्धारित किये जायेंगे ताकि सभी सी.आर.जेड. क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके।
3. लगभग 10,000 वर्ग किमी. से अधिक मैंग्रूव क्षेत्रों के चारों ओर बफर क्षेत्र को अलग रंग से चिह्नित किया जायेगा ताकि मैंग्रूव क्षेत्रों और बफर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से विभेद किया जा सके।
4. बफर क्षेत्र को भी सी.आर.जेड.—I क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
5. जोखिम रेखा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तय की जायेगी और इसे 1:25000 पैमाने के सी.जेड.एम. मानचित्र और अधिकृत पैमाने के मानचित्र पर चिह्नित किया जायेगा।
6. सी.आर.जेड.—II क्षेत्र वे क्षेत्र होंगे जिन्हें कि इस प्रकार निर्मित किया गया होगा कि कुल प्लॉट में बने हुए निर्मित प्लॉट का अनुपात 50 प्रतिशत से ज्यादा होगा।
7. सी.आर.जेड.—III क्षेत्रों में, मछुआरा समुदाय के गाँव, उनकी साझा संपत्तियाँ, मछली पकड़ने के घाट, मछली सुखाने के प्लेटफार्म/क्षेत्र, मछुआरा और स्थानीय समुदाय की ढांचागत सुविधाओं जैसे दवाखाना, सड़कें, विद्यालय इत्यादि को अधिकृत पैमाने के मानचित्र पर प्रदर्शित किया जायेगा।
8. सी.आर.जेड.—IV के जल क्षेत्र जैसे समुद्र, लगून, बैकवॉटर, क्रीक, खाड़ी, इस्चुअरी आदि को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा। जल क्षेत्रों के इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए नैवल-हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली शब्दावली को इस्तेमाल किया जायेगा।

9. जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्थानों तथा मछली प्रजनन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा।
10. जल क्षेत्रों में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल गुणवत्ता के मानकों के आधार पर, प्रदूषण स्तर को प्रदर्शित किया जायेगा।
11. सी.आर.जेड.-V क्षेत्रों में, भू-उपयोग मानचित्रों को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में अध्यारोपित किया जायेगा और इसमें सी.आर.जेड. I, II, III, IV को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।
12. समुद्र की ओर के क्षेत्र में मौजूदा प्रमाणीकृत विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।
13. चक्रवात, तूफान और सूनामी के समय बचाव कार्य में सुविधा हेतु चक्रवात से बचने के स्थानों, हवाई पट्टियों और अन्य ढांचागत संरचनाओं जैसे सड़क नेटवर्क को भी सी.जेड. एम. मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।

III. तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना का पुनरीक्षण

1. जहां कहीं भी संदेह हो ऐसे मामलों पर संबंधित राज्य/केन्द्रशासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल सेन्टर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल सेटलाइट इमेजनरी और भूमिगत स्तर पर सत्यता जांच के द्वारा सत्यापन करेगा।
2. मानचित्र में किये गये सुधारों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अभिलेखन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. तट की परिवर्तनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सी.जेड.एम. मानचित्रों को प्रत्येक 5 वर्ष में पुनरीक्षित किया जायेगा।

IV. सी.जेड.एम.पी. पर जनसमुदाय के मत

- अ. ड्राफ्ट सी.जेड.एम.पी. का, ई.पी.ए. 1986 के तहत लोगों के सुझावों और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर प्रचार किया जायेगा।
- ब. लोगों के सुझावों और आपत्तियों के आधार पर सी.जेड.एम.पी. को पुनरीक्षण किया जायेगा और इसे प्रमाणीकरण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- स. प्रमाणित सी.जेड.एम.पी. को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की वेबसाइट, संबंधित राज्य/केन्द्रशासित सी.जेड.एम.पी. की वेबसाइटों पर डाला जायेगा और इसकी मूल प्रति (हार्ड कॉपी) को पंचायत कार्यालय, जिला अधिकारी के कार्यालय आदि में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक II(पैराग्राफ 3, सब पैराग्राफ 3(ii) (ब))

पेट्रोलियम व रसायन उत्पादों की सूची जिनके भण्डारण की (एस.पी.सी.जेंड.-I(i) के बजाय एस.पी. सी.जेंड. में) अनुमति है

- (i) कच्चा तेल;
- (ii) लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस;
- (iii) मोटर स्प्रीट;
- (iv) कैरोसिन;
- (v) विमान ईंधन;
- (vi) हाई स्पीड डीजल;
- (vii) लुब्रीकेटिंग ऑयल;
- (viii) ब्यूटेन;
- (ix) प्रोपेन;
- (x) कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस;
- (xi) नेपथा;
- (xii) फर्नेस ऑयल;
- (xiii) लो सल्फर हैवी स्टॉक;
- (xiv) लिक्विफाइड नेचुरल गैस;
- (xv) खाद व खाद के उत्पादन हेतु कच्चा माल।

संलग्नक—III

एस.पी.सी.जेड.—III के निर्धारित क्षेत्रों में तट रिसोर्ट/होटल के निर्माण तथा एस.पी.सी.जेड.—III में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बाद सैलानियों/यात्रियों के अस्थाई रूप से ठहरने संबंधी दिशानिर्देश।

I. सैलानियों/यात्रियों के अस्थाई निवास हेतु एस.पी.सी.जेड.—I और II के निर्धारित क्षेत्रों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति के पश्चात् तट रिसोर्ट/होटलों के निर्माण निम्नांकित परिस्थितियों से संदर्भित होंगे:

- क. परियोजना प्रस्तावक, समुद्र की ओर की जोखिम रेखा और निम्न ज्वार रेखा तथा उच्च ज्वार रेखा के बीच किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा।
- ख. ऐसा प्रावधान है कि केन्द्र सरकार भौगोलिक स्थितियों और तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को ध्यान में रखते हुए तथा संबंधित कारणों को अभिलिखित करते हुए, कुछ शर्तों और प्रतिबंधों जो उस परिस्थिति के अनुरूप हों के साथ निर्माण कार्य की अनुमति दे सकती है।
- ग. निजी संपत्तियों के चारों ओर पौधों और कांटेदार तारों द्वारा चाहरदीवारी के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि इनके कारण लोगों की समुद्री किनारे तक पहुँच में कोई व्यवधान न हो।
- घ. रेत के टीलों को समतल नहीं किया जायेगा;
- च. खेल सुविधाओं के लिए, गोल पोस्ट, नेट पोस्ट और लम्प पोस्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के स्थाई निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
- छ. तहखाने के निर्माण की अनुमति इस आधार पर दी जा सकती है कि प्रस्तावक राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण से इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि निर्माण उस क्षेत्र में भू-गर्भीय जल के मुक्त प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा।
- ज. राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण इस प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का संदर्भ लेगा।
- झ. यद्यपि विकास रहित क्षेत्र में फ्लोर स्पेस इण्डेक्स की गणना के लिए किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है, सम्पूर्ण भू-खण्ड का क्षेत्रफल जिसमें वह भाग भी शामिल होगा जो विकास रहित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है को भी ध्यान में रखा जायेगा।
- ट. भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए तथा सभी मालों (फ्लोर) का कुल ढका हुआ क्षेत्र भूखण्ड के कुल आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना

चाहिए अर्थात् फ्लोर स्पेश इण्डेक्स 0.33 से अधिक नहीं होना चाहिए। खुला क्षेत्र समतल होगा और उचित वनस्पतियों से आच्छादित होगा;

- ठ. निर्माण कार्य आस-पास की स्थलाकृति एवं स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होगा;
- ड. निर्माण कार्य में छत की कुल ऊँचाई 9 मीटर से ज्यादा नहीं होगी व दो तल से ज्यादा (नीचे का तल व उसके ऊपर का तल) का निर्माण नहीं होगा;
- ढ. भूगर्भ जल को उच्च ज्वार रेखा में 200 मी. के नीचे से नहीं लिया जायेगा; 200-500 मी. के जोन में केन्द्रीय/राज्य भू-जल बोर्ड की सहमति से लिया जा सकता है;
- त. उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर की दूरी में बालू का खनन, समतल करना या बालू को खोदना केवल बिल्डिंग की बुनियाद, स्वीमिंग पुल को छोड़कर अनुमत नहीं होगा;
- द. परियोजना क्षेत्र में उपचारित उत्प्रवाह, ठोस कचरे, धुँआ तथा शोर के स्तर आदि की गुणवत्ता को सक्षम प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) कानून, 1986 के तहत तथा केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बनाये गये मानकों के अनुसार होगा;
- ध. उत्प्रवाहों तथा ठोस कचरे के उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्थायें अवश्य की जानी चाहिए; अनुपचारित उत्प्रवाह तथा ठोस कचरे को पानी में या तट पर फेंका या छोड़ा न जाय; तथा कोई भी उत्प्रवाह/ठोस कचरा समुद्र तट पर छोड़ा नहीं जायेगा इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए;
- य. समुद्र तट पर लोगों की पहुंच को अनुमति देने हेतु किन्हीं दो होटलों/बीच रिसोर्टों के मध्य कम से कम 20 मीटर की चौड़ाई का अन्तराल होना चाहिए। किसी भी स्थिति में कुल अन्तराल 500 मी. से कम नहीं होगा; तथा
- र. यदि परियोजना में वन भूमि को अवनीय उद्देश्यों के लिए शामिल किया जाना है तो वन (संरक्षण) कानून, 1980 के तहत, सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा केन्द्र व राज्य कानूनों के लागू होने वाली सभी आवश्यकताओं को परियोजना द्वारा पूर्ण किया जायेगा;

ल. राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के पर्यटन विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

II. पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों (जैसेकि समुद्री पार्क, मैयूव, मूंगा भित्ती, मछलियों का जनन व पालने का क्षेत्र, वन्यजीव पर्यावास तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित किया गया हो) समुद्रतटीय रिसोर्ट/होटलों के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

संलग्नक-IV

सी.आर.जेड. अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं को अनुमति प्राप्त करने हेतु फार्म 1

प्रमुख जानकारी:

परियोजना का नाम:

विचार किया जाने वाला स्थान या उसका विकल्प:

परियोजना का आकार (कुल क्षेत्रफल के आधार पर):

क्षेत्र का सी.आर.जेड. वर्गीकरण:

परियोजना की अनुमानित लागत:

संपर्क संबंधी जानकारी

(II) गतिविधि:

1. निर्माण, संचालन या किसी और को परियोजना संबंधी कार्य में शामिल करना जिससे कि उस स्थान (स्थलाकृति, भूपयोग, जलाशयों में बदलाव आदि) पर भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं।

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि

हाँ/नहीं

जानकारी विस्तार में
(अनुमानित मात्रा/दर,
जहां भी संभव हो) स्रोत के
साथ सूचना आंकड़ों के
द्वारा

1.1 भूपयोग, स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी बदलाव

जिसमें भूमि उपयोग में बढ़ने वाली तीव्रता भी शामिल

है (स्थानीय भूमि उपयोग योजना के आधार पर)

1.2 सी.आर.जेड. वर्गीकरण का विवरण जैसाकि तटीय जोन

प्रबंधन योजना में अनुमोदित है?

1.3 यदि सी.आर.जेड.-I क्षेत्र में स्थित है?

1.4 सी.आर.जेड.-I क्षेत्रों से दूरी।

1.5 यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मानचित्रित जोखिम

क्षेत्र में स्थित है?

1.6 यदि क्षेत्र तूफान, सुनामी, ऊँची ज्वार लहरें, सबडक्शन,

भूकंप आदि के लिए संवेदनशील है।

- 1.7 यदि क्षेत्र नमकीन पानी के प्रवेश करने के प्रति संवेदनशील है?
- 1.8 वर्तमान भूमि, हरित क्षेत्र एवं बिल्डिंगों के लिए अनुमति है?
- 1.9 भूमि के नये उपयोग हेतु तैयार करना?
- 1.10 पूर्व निर्माण जांच जैसे बोरहोल, मशदा परीक्षण?
- 1.11 निर्माण कार्य?
- 1.12 ढहाने संबंधी कार्य?
- 1.13 निर्माण कार्य हेतु स्थायी क्षेत्र या निर्माण कार्य के मजदूरों हेतु निवास स्थान?
- 1.14 भूमि के ऊपर की बिल्डिंगे, आकृतियां या मिट्टी का काम जैसे सीधी आकृतियां, कटाई-भराई या खुदाई
- 1.15 भूगर्भीय कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना शामिल है?
- 1.16 सुधार (रिकलेमेशन) संबंधी कार्य?
- 1.17 मिट्टी निकालना/सुधार कार्य/भू-भराव/खुदाई में निकली मिट्टी आदि?
- 1.18 तट से दूरी पर (ऑफशोर) आकृतियाँ?
- 1.19 उत्पादन एवं निर्माण प्रक्रियायें?
- 1.20 वस्तुओं या सामानों के भण्डारण के लिए सुविधायें?
- 1.21 ठोस कचरा या द्रवीय उत्प्रवाह के उपचार या निस्तारण के लिए सुविधायें?
- 1.22 निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए लम्बे समय तक निवास संबंधी सुविधायें?
- 1.23 निर्माण या संचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री ट्रैफिक?
- 1.24 नई रोड, रेल, हवा-जल संबंधी या अन्य परिवहन ढांचे जिसमें नये या बदले हुए मार्ग तथा स्टेशन, पत्तन, हवाई अड्डे आदि?
- 1.25 वर्तमान परिवहन मार्गों के बन्द होने या बदले जाने अथवा ऐसे ढांचे जिसके कारण यातायात के संचालन में बदलाव
- 1.26 नई या परिवर्तित संचार लाइनें या पाईप लाइनें?
- 1.27 अवरोधन, बांध निर्माण, पुलिया बनाना, पुनः संरेखण अथवा जल बहाव या एक्वेफर के जल

तंत्र में बदलाव?

1.28 धारा या नदी के पार?

1.29 जल का भूगर्भीया सतही जल स्रोतों से निकाला

जाना या स्थानान्तरण?

1.30 भू-सतह या जलाशयों में परिवर्तन जिससे जल

निकास या बहाव प्रभावित होगा?

1.31 निर्माण, संचालन या कार्य ठेके पर देने हेतु लोगों

या वस्तुओं का परिवहन?

1.32 दीर्घकालिक विखण्डन या ठेके पर कार्य या

पुनरोद्धार कार्य?

1.33 गतिविधियों के जारी रहने के दौरान पर्यावरण पर

पड़ सकने वाले प्रभाव?

1.34 एक क्षेत्र में अस्थायी या स्थायी रूप से लोगों का

आना?

1.35 वाह्य या विदेशी प्रजातियों को क्षेत्र में लाना?

1.36 स्थानीय प्रजातियों या जीनिक विविधता की हानि?

1.37 कोई अन्य कार्य?

2. परियोजना के संचालन या निर्माण के लिए उपयोग होने वाले प्राकृतिक संसाधन (जैसे कि भूमि, जल, वस्तुएं या ऊर्जा विशेषतः ऐसा कोई संसाधन जोकि अनवीनीकरण या कम आपूर्ति में उपलब्ध हो)

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि

हाँ/नहीं

जानकारी विस्तार

में (अनुमानित मात्रा/दर,
जहां भी संभव हो) स्रोत के
साथ सूचना आंकड़ों के
द्वारा

2.1 भूमि विशेषतः अविकसित या कृषि योग्य जमीन (हे.)

2.2 जल (अनुमानित स्रोत एवं प्रतियोगी उपयोगकर्ता)

यूनिट: के.एल.डी.

- 2.3 खनिज (एम.टी.)
- 2.4 निर्माण सामग्री—पत्थर, कुल सामान, बालू/मिट्टी
(अनुमानित स्रोत—एम.टी.)
- 2.5 वन एवं इमारती लकड़ी (स्रोत—एम.टी.)
- 2.6 ऊर्जा के अन्तर्गत विद्युत एवं ईंधन (स्रोत एवं
प्रतियोगी उपयोगकर्ता) यूनिट: ईंधन (एम.टी.), ऊर्जा (एम.डब्ल्यू.)
- 2.7 कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (उपयुक्त मानक इकाईयों
का प्रयोग)

3. उपयोग, संग्रहण, परिवहन, रखरखाव या पदार्थों या सामग्रियों का उत्पादन, जोकि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के प्रति हानिकारक हो सकता है या मानव स्वास्थ्य से जुड़ा वास्तविक या संभावित खतरा पैदा कर सकता है।

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	जानकारी विस्तार में (अनुमानित मात्रा/दर, जहां भी संभव हो) स्रोत के साथ सूचना आंकड़ों के द्वारा
3.1 पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जोकि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (पौधे, जीव व जलापूर्ति) के लिए खतरनाक (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) हो		
3.2 रोगों के होने या रोगों के वाहकों (उदाहरण के लिए कीट या जलजनित रोग) के प्रभावों में परिवर्तन		
3.3 लोगों के हित को प्रभावित करता है। उदाहरण जीवन स्थितियों में बदलाव?		
3.4 संवेदनशील लोगों का ऐसा समूह जोकि परियोजना द्वारा प्रभावित हो सकता है। जैसे—अस्पताल के मरीज, बच्चे, बुजुर्ग आदि		
3.5 कोई अन्य कारण		

4. निर्माण कार्य या संचालन या ठेके पर काम देने के दौरान (एम.टी./माह) निकला ठोस कचरा

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	जानकारी विस्तार में (अनुमानित मात्रा/दर, जहां भी संभव हो) स्रोत के साथ सूचना आंकड़ों के द्वारा
4.1 बेकार, अतिरिक्त या खुदाई के दौरान निकला कचरा		
4.2 नगरीय कचरा (घरेलू और या वाणिज्यिक कचरा)		
4.3 खतरनाक कचरा (खतरनाक कचरा प्रबंधन नियम के अनुसार)		
4.4 अन्य औद्योगिक प्रक्रिया से निकला कचरा		
4.5 अतिरिक्त सामान		
4.6 सीवेज बहाव या उत्प्रवाह उपचार संयंत्र से निकला बहाव		
4.7 निर्माण या ढहाव में निकला कचरा		
4.8 अनावश्यक मशीनरी या औजार		
4.9 संक्रमित मशदा या अन्य सामग्री		
4.10 कृषि कार्य में निकलने वाला कचरा		
4.11 अन्य ठोस कचरे		

5. प्रदूषक या किसी अन्य खतरनाक, विषाक्त या जहरीले पदार्थ

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	जानकारी विस्तार में (अनुमानित मात्रा/दर, जहां भी संभव हो) स्रोत के साथ सूचना आंकड़ों के द्वारा
5.1 जीवाश्म ईंधन के स्थायी या अस्थायी स्रोत पर होने वाले दहन से निकलने वाला धुआ		
5.2 उत्पादन प्रक्रियाओं से निकलने वाला धुआ।		
5.3 सामान के रखरखाव जिसमें उसका संग्रहण या परिवहन शामिल है से निकलने वाला धुआ		
5.4 निर्माण कार्य जिसमें उद्योग व औजार शामिल हैं से निकलने वाला धुआ		
5.5 सामान के रखरखाव में निकलने वाली धूल या बदबू जिसमें निर्माण संबंधी सामान, सीवेज व कचरा शामिल हैं		
5.6 कचरे के भस्मीकरण से निकलने वाला धुआ		
5.7 कचरे को खुली हवा में जलाने से निकलने वाला धुआ		

(जैसे कटाई में निकला सामान या बची-खुची निर्माण सामग्री)
5.8 किसी अन्य स्रोत से निकलने वाला धुँआ

6. शोर या कंपन के पैदा होने तथा रोशनी या ऊष्मा के उत्सर्जित होने से

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	जानकारी विस्तार में (अनुमानित मात्रा/दर, जहां भी संभव हो) स्रोत के साथ सूचना आंकड़ों के द्वारा
-----------------------------------	----------	--

6.1 औजारों के संचालन में उपयोग जैसे इंजन, वेंटिलेशन
प्लान्ट, क्रशर्स

6.2 औद्योगिक या समान प्रक्रियाओं से

6.3 निर्माण या ढहाव कार्य से

6.4 धमाके या पाइलिंग से

6.5 निर्माण या परिवहन संचालन से

6.6 रोशनी या ठण्डा करने की व्यवस्था से

6.7 किसी अन्य स्रोत से

7. प्रदूषकों के भूगर्भ या सीवर, सतही जल, भूगर्भ जल, तटीय जल या समुद्र में छोड़े जाने से
भूमि या पानी के संक्रमण के खतरे

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	जानकारी विस्तार में (अनुमानित मात्रा/दर, जहां भी संभव हो) स्रोत के साथ सूचना आंकड़ों के द्वारा
-----------------------------------	----------	--

7.1 खतरनाक वस्तुओं के रखरखाव, संग्रहण, उपयोग या
गिरने से।

7.3 हवा में उत्सर्जित प्रदूषकों के भूमि या जल में इकट्ठा होने से

7.4 किसी अन्य स्रोत से

7.5 इन स्रोतों से प्रदूषकों के पर्यावरण में लम्बे समय तक
बने रहने का खतरा है क्या?

8. परियोजना के निर्माण कार्य या संचालन के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा जोकि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है।

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	जानकारी विस्तार में (अनुमानित मात्रा/दर, जहां भी संभव हो) स्रोत के साथ सूचना आंकड़ों के द्वारा
8.1 खतरनाक पदार्थों के संग्रहण, रखरखाव, उपयोग या उत्पादन के दौरान होने वाला धमाका, बहना, आग आदि से		
8.2 किसी अन्य स्रोत से		
8.3 क्या परियोजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकती है जिससे पर्यावरणीय क्षति होगी (जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बादल का फटना आदि)?		

9. कारक जिनको ध्यान दिया जाना चाहिए (जैसे परिणामी विकास) जिससे पर्यावरणीय प्रभाव या उस स्थान पर नियोजित या वर्तमान गतिविधियों का एक बड़ा संभावित प्रभाव हो सकता है

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	जानकारी विस्तार में (अनुमानित मात्रा/दर, जहां भी संभव हो) स्रोत के साथ सूचना आंकड़ों के द्वारा
9.1 विकास को सहयोग देने की ओर उन विकास परियोजनाओं या विकास गतिविधियों का जिसका प्रभाव पर्यावरण पर हो सकता है, उदाहरण मूलभूत ढांचे के निर्माण (रोड, विद्युत आपूर्ति, कचरा या बेकार जल का उपचार आदि), आवास-विकास निष्कर्षण उद्योग आपूर्ति उद्योग अन्य		
9.2 स्थल की प्रयोग-पश्चात् स्थिति के लिए, जिसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव हो सकता है		
9.3 बाढ़ की घटनाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना		
9.4 समान प्रभावों वाली अन्य विद्यमान या योजनाबद्ध परियोजनाओं से निकटता के कारण संचित प्रभाव होना		

III. पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्रम सं० क्षेत्र	नाम/पहचान	हवाई दूरी (15 किमी. के अन्दर) प्रस्तावित परियोजना स्थल सीमा
1	क्षेत्र जो अन्तर्राष्ट्रीय सहमति पत्र, राष्ट्रीय या स्थानीय कानून के अन्तर्गत पारिस्थितिकीय स्थलाकृति, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के तहत संरक्षित हैं	
2	क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय कारणों से संवेदनशील या महत्वपूर्ण हैं — नमभूमियां, जल बहाव क्षेत्र या अन्य जलाशय, तटीय क्षेत्र, बायोस्फियर, पर्वत वन	
3	क्षेत्र जो संरक्षित, महत्वपूर्ण या संवेदनशील पौध या जन्तु प्रजातियों द्वारा जनन, घोंसला बनाने, विचरण करने, आराम करने, मौसमीय स्थल, प्रवासन के लिए प्रयोग किये जाते हैं	
4	इनलैण्ड, तटीय, समुद्री या भूमिगत जल।	
5	राज्य, राष्ट्रीय सीमायें	
6	रास्ते या सुविधायें जो जनता द्वारा मनोरंजन या अन्य पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रों के रूप में प्रयोग किये जाते हैं	
7	सुरक्षा संबंधी क्षेत्र	
8	घनी आबादी या निर्मित क्षेत्र	
9	क्षेत्र जो मानव के लिए संवेदनशील भू उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है (अस्पताल, विद्यालय, पूजा स्थल, समुदायिक सुविधायें)	
10	क्षेत्र जो महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता या संसाधनों की कमी वाले हों (भूगर्भीय जल संसाधन, सतही संसाधन, वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, मछली पालन, पर्यटन, खनिज)	
11	क्षेत्र जो पहले से प्रदूषण या पर्यावरणीय क्षतिग्रस्त हैं (वे जो वर्तमान कानूनी पर्यावरणीय मानकों के परे जा चुके हैं)	
12	क्षेत्र जो प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदी हो जहां परियोजना के कारण पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो सकती हैं (भूकंप, जमीन का खिसकना, भूस्खलन, अपरदन, बाढ़ या तीव्र या प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां)	

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2010

S.O. 2291(E).— WHEREAS the Central Government vide its notification number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991, (hereinafter referred to as the said notification), declared Coastal Regulation Zone and imposed certain restrictions on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zones for its protection;

AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court in the Order dated 19th April, 1993 in Writ Petition No.664 of 1993, directed the Central Government and the coastal States that 'there is 6000 km long coastline of India and it is the responsibility of coastal States and Union territories in which these stretches exists to see that both the notifications are complied with and enforced';

AND WHEREAS, in compliance to the Orders of the Hon'ble Supreme Court, the coastal States and Union territory, prepared the Coastal Zone Management Plans which were approved with condition and modifications dated the 27th September, 1996;

AND WHEREAS, the said notification was amended, from time to time, based on recommendations of various committees, judicial pronouncements, representations from State Governments, Ministries and Departments of the Central Government, and the general public, consistent with the basic objective of the said notification;

AND WHEREAS, perceiving the continuing difficulties posed by the said notification in its effective implementation for the sustainable development of coastal regions as well as conservation of coastal resources, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests constituted an Expert Committee under the Chairmanship of Prof. M. S. Swaminathan, with experts in the areas of environmental law, marine biodiversity, marine geology, environmental economics, socio-economic, remote sensing, coastal engineering, urban planning and marine fisheries, to carry out a comprehensive review of the said notification (including all its amendments) in the light of findings and recommendations of previous committees, judicial pronouncements, representations of various stakeholders, and to suggest suitable amendments, if necessary, to make the coastal regulatory framework consistent with well established scientific principles of coastal zone management;

AND WHEREAS, the above referred Expert Committee had submitted its report to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests on the 14th February, 2005 containing specific recommendations to build on the strengths of existing regulations and institutional structures and fill gaps for conservation and improving the management of the coastal resources by enhancing the living and non-living resources of the coastal zone; by ensuring protection to coastal populations and structures from risk of inundation from extreme weather and geological events; and by ensuring that the livelihood security of populations living in islands are strengthened;

AND WHEREAS, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests issued a draft notification on the 22nd July, 2008 vide number S.O.1761(E), under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) inviting suggestions and objections from the public likely to be affected thereby;

AND WHEREAS, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (hereinafter referred to as the MoEF) received large number of suggestions and objections on the draft notification which were examined by an Expert Committee constituted under the Chairmanship of Prof. M. S. Swaminathan;

AND WHEREAS, the Expert Committee under the Chairmanship of Prof. M. S. Swaminathan after detailed examination of the comments received on the draft Coastal Management Zone Notification, 2008 (hereinafter referred to as the CMZ Notification, 2008) and consultations with the stakeholders submitted the Report titled "Final Frontier" on the 16th July, 2009 and this Report recommended to let the draft Coastal Management Zone Notification, 2008 lapse and to strengthen the Coastal Regulation Zone Notification, (hereinafter referred to as the CRZ Notification) 1991. The Ministry of Environment and Forests accepted the recommendations of this Report and let the draft CMZ Notification, 2008 lapse;

AND WHEREAS, the Expert Committee further noted that, the Indian coast is doubly vulnerable today. On one hand, it is facing unprecedented pressures because of industrial and urban development; on the other, it will be threatened by climate change-related devastation — from growing intensities of cyclonic storms to sea surges and eventual sea level rise. All this requires increased attention and vigilance for the protection of the coasts and the people who live there. It is also clear that coastal areas are the habitats of fishing communities. These communities are in double danger as well — ironically, from conservation on one hand and development on the other. Future policies for coastal area management must reverse these trends and find approaches to conserve and protect vulnerable ecosystems and secure the livelihoods

and habitats of its people. This is the challenge. Further, the Committee made several recommendations for strengthening the coastal zone management approach in the country;

AND WHEREAS, the Central Government, undertook consultations with the fishermen communities, local communities and NGOs from August, 2009-March, 2010 and these consultations were organized by Centre of Environmental Education (hereinafter referred to as the CEE), who submitted the Report of the consultation process in 25th March, 2010;

AND WHEREAS, the Central Government after taking into account the Report titled "Final Frontier" and the report submitted by CEE regarding special consideration to be given to some of the areas in the coastal region in-view of the demographic pressure, geographical and ecological uniqueness brought out a pre-draft Coastal Regulation Zone Notification, 2010 on 31st April, 2010 which was put on the MoEF website in nine coastal local languages, Gujarati, Konkani, Marathi, Kannada, Malayalam, Telugu, Tamil, Oriya and Bengali including Hindi and English. Further, a period of thirty days was given to seek comments on pre draft Coastal Regulation Zone Notification, 2010;

AND WHEREAS, as the Central Government received several comments on the pre-draft Coastal Regulation Zone Notification, 2010 from public, NGOs etc., including Central and State Governments;

AND WHEREAS, the Central Government, taking into account the outcome of the above consultation process held by Centre of Environmental Education and the recommendations made in the "Final Frontier", 2009, comments received on pre-draft Coastal Regulation Zone Notification, 2010, proposes to make the following proposal under sub-section (1) and clause (v) of sub section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991, in so far as it relate to the conservation and protection of the coastal stretches of the country, and the same is published for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft proposal shall be taken into consideration by the Central Government on and after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the this notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS, any person interested in making any objections or suggestions on the draft proposal may forward the same in writing within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003, or at e-mail address: secy@menf.nic.in.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, with a view to ensure livelihood security to the fisher communities and other local communities, living in the coastal areas, to conservation and protection of coastal stretches, its unique environment and its marine area and to promote development through sustainable manner based on scientific principles taking into account the dangers of natural hazards in the coastal areas, sea level rise due to global warming, does hereby, declare the coastal stretches of the country and the water area upto its territorial water limit, excluding the islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep and the marine areas surrounding these islands upto its territorial limit, as Coastal Regulation Zone(CRZ) and restricts the setting up and expansion of any industry, operations or processes and manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Hazardous Substances (Handling, Management and Transboundary Movement) Rules, 2009 in the aforesaid CRZ. .

2. Now therefore in exercise of powers conferred by clause (d) of sub rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986 and all powers vesting in its behalf, the Central Government hereby declares the following areas as CRZ and imposes with effect from the date of this notification the following restrictions on the setting up and expansion of industries, operations or processes etc., in the said CRZ:-

- (i) the land area from High Tide Line (HTL) to 500mts on the landward side along the sea front.
- (ii) CRZ shall apply to the land area between HTL to 100 mts or width of the creek whichever is less on the landward side along the tidal influenced water bodies that are connected to the sea and the distance upto which development along such tidal influenced water bodies is to be regulated shall be governed by the distance upto which the tidal effects are experienced which shall be determined based on salinity concentration of 5 parts per thousand (ppt) measured during the driest period of the year and distance upto which tidal effects are experienced shall be clearly identified and demarcated accordingly in the Coastal Zone Management Plans (CZMPs).

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph the expression tidal influenced water bodies means the water bodies influenced by tidal effects from sea and includes seas,

bays, estuaries, creeks, backwaters, lagoons, holding ponds connected to the sea or creek etc.

- (iii) the land area falling between the hazard line and 500mts from HTL on the landward side. In case of seafront and between the hazard line and 100mts line in case of tidal influenced water body. Hazard line means the line demarcated by Ministry of Environment and Forests (MoEF) through Survey of India (SoI) taking into account tides, waves and sea level rise and shoreline changes.
- (iv) land area between HTL and Low Tide Line (LTL) which will be termed as the intertidal zone.
- (v) the water area between the LTL to the territorial water limit (12 Nm) in case of sea and the water area between LTL at the bank to the LTL on the opposite side of the bank, in case of tidal influenced water bodies.

2.1 For the purposes of this notification, the HTL means the line on the land upto which the highest water line reaches during the spring tide and shall be demarcated uniformly in all parts of the country by the demarcating authority or authorities so authorized by the Central Government in accordance with the general guidelines issued at Annexure-I. High Tide Line shall be demarcated within one year from the date of issue of this notification.

3. Prohibited activities within CRZ,- The following are declared as prohibited activities within the Coastal Regulation Zone,-

(i) Setting up of new industries and expansion of existing industries except,-

(a) those directly related to waterfront or directly needing foreshore facilities;

Explanation: For the purposes of the clause the expression "Foreshore facilities" means those activities permissible under this notification and they require waterfront for their operations such as ports and harbours, jetties, quays, wharves, erosion control measures, breakwaters, pipelines, lighthouses, navigational safety facilities, coastal police stations etc.;

(b) projects of Department of Atomic Energy;

(c) non-polluting industries in the field of Information Technology and other service industries in the CRZ of Special Economic Zone (SEZ);

- (d) facilities for generating power by non-conventional energy sources and setting up of desalination plants in the areas not classified as CRZ-I(i);
 - (e) development of green field Airport at Navi Mumbai.
- (ii) Manufacture or handling oil storage or disposal of hazardous substance as specified in the notification of Ministry of Environment and Forests, No. S.O.594 (E), dated the 28th July 1989, S.O.No.966(E), dated the 27th November, 1989 and GSR 1037 (E), dated the 5th December, 1989 except,-
- (a) transfer of hazardous substances from ships to ports, terminals and refineries and vice versa;
 - (b) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II appended to this notification and facilities for regasification of Liquefied Natural Gas (LNG) in the areas not classified as CRZ-I(i) subject to implementation of safety regulations including guidelines issued by Oil Industry Safety Directorate in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and guidelines issued by Ministry of Environment and Forests and subject to further terms and conditions for implementation of ameliorative and restorative measures in relation to environment as may be stipulated by Government of India in Ministry of Environment and Forests.
- Provided that facilities for receipt and storage of fertilizers and raw materials required for manufacture of fertilizers like ammonia, phosphoric acid, sulphur, sulphuric acid, nitric acid etc., shall be permitted within the said zone in the areas not classified as CRZ-I(i).
- (iii) Setting up and expansion of fish processing units including warehousing (excluding hatchery and natural fish drying in permitted areas):

Provided that the existing (prior to 19.2.1991) fish processing units for modernisation purposes may utilise 25% additional plinth area required for additional equipment and pollution control measures only subject to existing Floor Space Index or Floor Area Ratio norms and subject to the condition that additional plinth area shall not be towards seaward side of existing (prior to 19.2.1991) unit and also subject to approval of State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC).

- (iv) Setting up and expansion of units or mechanism for disposal of wastes and effluents except facilities required for, -
- (a) discharging treated effluents into the water course with approval under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
 - (b) storm water drains and ancillary structures for pumping;
 - (c) treatment of waste and effluents arising from hotels and beach resorts located in CRZ areas other than CRZ-I and disposal of treated wastes and effluents;
- (v) Discharge of untreated waste and effluents from industries, cities or towns and other human settlements, schemes shall be implemented by the concerned authorities for phasing out existing practices, if any, within a time period not exceeding two years from the date of commencement of this notification.
- (vi) Dumping of city or town waste including construction debris, industrial solid waste, fly ash for the purpose of land filling or otherwise; any existing practice, if any, shall be phased out within a period of one year from date of commencement of this notification.
- (vii) The State Government and Union territory Administration shall prepare an Action Plan for sub-paragraphs (v) and (vi) of paragraph 3 and allocate adequate budget to deal with pollution of coastal areas and waters in a time bound manner and an action in this regard shall be submitted to MoEF within six months from date of issue of this notification for approval.
- (viii) The Action Plans referred to-in sub-paragraph (vii) shall be implemented by the State or Union Territory Government in a time bound manner.
- (ix) MoEF or Central Pollution Control Board (CPCB) shall monitor the implementation of the Action Plan.
- (x) Land reclamation, bunding or disturbing the natural course of seawater except those, -
- (a) required for setting up, construction or modernisation or expansion of foreshore facilities like ports, harbours, jetties, wharves, quays, slipways, bridges, sealinks, roads on stilts, coastal police station and helipad for defence and security purpose and for other facilities that are essential for activities permissible under the notification;

- (b) measures for control of erosion, based on scientific studies including Environmental Impact Assessment (hereinafter referred to as the EIA) studies
 - (c) maintenance or clearing of waterways, channels and ports, based on scientific studies including EIA studies;
 - (d) measures to prevent sand bars, installation of tidal regulators, laying of storm water drains or for structures for prevention of salinity ingress and freshwater recharge based on scientific studies including EIA studies carried out by reputed national agencies
- (xi)(a) MoEF through reputed scientific institution shall undertake a study to determine the coastal stretch that are undergoing shoreline changes, and classify such coastal stretches as 'high eroding sites', 'medium eroding sites' and 'low or stable sites'. MoEF with State Authorities or Government Departments and scientific institutions shall identify the causes of such shoreline changes and take necessary measures to minimise such erosion within a stipulated period of time not exceeding two years from the date of issue of this notification.
- (b) Till issue of this notification no port projects shall be permitted in the high eroding sites.
 - (c) These classifications of the stretches indicating the shoreline changes shall be mapped on the Coastal Zone Management Plans.
- (xii) Reclamation for commercial purposes such as shopping and housing complexes, hotels and entertainment activities.
- (xiii) Mining of sand, rocks and other sub-strata materials except,-
- (a) those rare minerals not available outside the CRZ area,
 - (b) exploration and exploitation of Oil and Natural Gas.
- (xiv) (a) Drawal of groundwater and construction of mechanisms therefore, within 200mts of HTL; except in the areas which are inhabited by the local communities.
- (b) In the area between 200mts-500mts zone it shall be permitted only when done manually through ordinary wells for drinking, horticulture, agriculture and fisheries:

Provided that the drawal of groundwater is permitted where no other source of water is available and when done manually through ordinary wells or hand pumps, for drinking and domestic purposes, in the zone between 500metres to 200metres from HTL in case of sea, bays and estuaries and within 200m or the CRZ, whichever is less, from HTL in case of estuaries, creeks and backwaters subject to such restrictions, as may be deemed necessary, in areas affected by seawater intrusion, that may be imposed by an Authority designated by the State Government or Union Territory Administration;

(xv) Construction activities in CRZ-I except as specified in para 8 of this notification.

(xvi) Any construction activity between LTL and HTL except facilities for carrying treated effluents and wastewater discharges into the sea, facilities for carrying seawater for cooling purposes, oil , gas and similar pipelines and facilities essential for activities permitted under this notification.

(xvii) Dressing or altering the sand dunes, hills, natural features including landscape changes for beautification, recreation and other such purpose.

4. Regulation of permissible activities in CRZ area.- The following are the regulation of permissible activities (all other activities except those prohibited in paragraph-3 above will be regulated as under),-

(i) (a) clearance shall be given for any activity within the CRZ only if it requires waterfront and foreshore facilities;

(b) for those projects which are listed under this notification and also attract Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 (S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006), for such projects clearance under EIA Notification only shall be required subject to being recommended by the concerned State or Union Territory Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the CZMA).

(ii) following activities shall require clearance from MoEF, Government of India, namely,-

(a) construction activities relating to projects of Department of Atomic Energy or Defence requirements for which foreshore facilities are essential such as, slipways, jetties, wharves, quays; except for classified operational component of defence projects.

- (b) the projects referred to in item (a) shall be considered by a separate procedure which shall be notified by the Ministry.
 - (c) residential buildings, office buildings, hospital complexes, workshops shall not come within the definition of operational requirements except in very special cases and hence shall not normally be permitted in the CRZ;
 - (d) the clearance granted shall be valid for a period of five years for the commencement of construction or operation;
 - (e) construction and operation for ports and harbours, jetties, wharves, quays, slipways, shipyards and ship construction yards;
 - (f) construction and operation of breakwaters, groynes, erosion control measures;
 - (g) construction, operation of lighthouses;
 - (h) laying of pipelines, conveying systems, transmission line;
 - (i) exploration and extraction of oil and natural gas and all associated activities and facilities thereto;²
- (iii) Foreshore requiring facilities for transport of raw materials, facilities for intake of cooling water and outfall for discharge of treated wastewater or cooling water from thermal power plants;
- (iv) Housing schemes in Coastal Regulation Zone as specified in paragraph 8 of this notification;
- (v) Mining of rare minerals;
- (vi) Specified activities or facilities in SEZ subject to one time approval by Government of India in the MoEF to such activities based on Master Plan of SEZ, special distribution of projects to be located in CRZ and such other information as may be required for the purpose;
- (vii) Facilities for generating power by non-conventional energy resources, desalination plants and weather radars;
- (viii) Demolition and reconstruction of (a) buildings of archaeological and historical importance, (ii) heritage buildings; and buildings under public use.

- (ix) Public use buildings shall include building for the purposes of worship, education, medical care and cultural activities;
- (x) Construction more than 20,000sq mts built-up area shall be approved in accordance with EIA Notification, 2006 and in case of projects less than 20,000sq mts built-up area shall be approved by the concerned planning authorities in accordance with this notification after obtaining recommendations from the concerned CZMA.

4.2 Procedure for clearance of permissible activities.- All projects attracting this notification shall be accorded clearance as per the following procedure, namely:-

- (i) The project authorities shall submit the following application seeking prior clearance from CRZ Notification to the concerned Coastal Zone Management Authority,-
 - (a) Form-1 (Annexure-IV of the Notification);
 - (b) rapid EIA Report including marine and terrestrial EIA. Comprehensive EIA for port and foreshore requiring projects as per guidelines issued by MoEF from time to time;
 - (c) Disaster Management Report and Risk Management Report;
 - (d) CRZ map indicating HTL and LTL demarcated by an authorized agency (1:4000 scale);
 - (e) Project layout superimposed on the above map indicated at (d) above;
 - (f) The CRZ map shall cover 7km radius around the project site.
 - (g) The CRZ map shall indicate the CRZ-I, II, III and IV areas;
 - (h) No Objection Certificate from the concerned Pollution Control Boards or Committees for the projects which envisage discharge of effluents, solid wastes, sewage etc.;
- (ii) The concerned CZMA shall examine the above documents in accordance with the approved CZMP and CRZ notification and make recommendations within a period of forty five days from date of receipt of above document to,-
 - (a) SEAC or EAC in case of the project attracting EIA notification, 2006;
 - (b) MoEF or State Government for the project attracting CRZ notification;
- (iii) MoEF or State Government shall consider such projects for clearance based on the recommendations of the concerned CZMA within a period of sixty days.

- (vi) Validity of the project,- The clearance accorded to the projects under CRZ notification shall be valid for the period of five years from date of issue of the clearance.
- (v) Post clearance monitoring,- (a) it shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year;
- (b) all such compliance reports submitted by the project management shall be public documents;
- (c) copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority;
- (d) the latest such compliance report shall also be displayed on the website of the concerned regulatory authority.
- (vi) Transparency of clearance procedure,- to maintain transparency in the working of the CZMAs it shall be the responsibility of the CZMA to create a dedicated website and post the agendas, minutes, decision taken, clearance letters, violations, action taken, court cases etc., including the CZMPs.

5. Preparation of Coastal Zone Management Plans (hereinafter referred to as the CZMPs).

- (i) It shall be the responsibility of the MoEF to get the CZMPs prepared through reputed National scientific institution including the National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM) of MoEF in consultation with the respective State or Union territory Governments and other stakeholders. MoEF shall provide the technical and financial support for preparing the CZMPs.
- (ii) The hazard line shall be mapped by MoEF through Survey of India all along the coastline of the country and the hazard line shall be demarcated taking into account, tide, waves, sea level rise and shoreline changes.
- (iii) For the purpose of depicting the flooding due to tides, waves and sea level rise in the next fifty and hundred years, the contour mapping of the coastline shall be carried out at 0.5m interval upto 7km from HTL on the landward side, and the shoreline changes shall be demarcated based on historical data by comparing the previous satellite imageries with the recent satellite imageries.

- (iv) Mapping of the hazard line shall be carried out in 1:25,000 scale for macro scale land use planning and also on 1:10,000 scale or cadastral scale for local level mapping.
- (v) The coastal States and Union Territory shall prepare within a period of one year from the date of this notification, CZMPs in 1:25,000 scale map identifying and classifying the CRZ areas within the respective territories in accordance with the guidelines given in Annexure-I of the notification.
- (vi) The hazard line shall be taken into consideration while preparing the land use plan of the coastal areas.
- (vii) The draft CZMPs shall be submitted to the concerned CZMA who shall give wide publicity and invite comments from stakeholders to the draft CZMPs in accordance with the procedure laid down in Environment (Protection) Act, 1986.
- (viii) The State/Union Territory shall prepare the final Coastal Zone Management Plan within period of six months and obtain approval from the Central Government in MoEF.
- (ix) MoEF shall consider and approve the CZMPs within a period of three months from the date of receipt of the final CZMPs;
- (x) Within the framework of such approved plans, all development and activities listed in this notification shall be regulated by the State Government, Union Territory Administration, the local authority or the concerned CZMA as the case may be in accordance with provisions of this notification;
- (xi) Based on the request received by MoEF from the concerned State or Union Territory, the CZMPs can be revised after five years from date of finalization.
- (xii) Till such time the new CZMPs in accordance with CRZ, 2010 are approved, the approved CZMPs under Coastal Regulation Zone Notification, 1991 shall be adhered to.

6. Enforcement of the notification -

- (i) Violations under Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 1991,-
 - (a) the State or Union territory CZMA shall identify the violations of CRZ Notification, 1991 within a period of three months from date of issue of this notification and take necessary action in accordance with the Environment (Protection) Act, 1986 within a period of six months from the date of issue of this notification;

- (b) all violations of the CRZ Notification, 1991 which have been identified shall be acted upon by the respective State or Union Territory CZMAs within a period of six months from the date of issue of this notification;
- (c) details of all violations of CRZ Notification, 1991 and action taken shall be listed on the website of the concerned CZMA and MoEF specially created for Coastal Zone Management.

(ii) Enforcement of CRZ, Notification, 2010-

- (a) the MoEF, Delhi, Environment Departments of the concerned State Government or Union territory or the concerned departments or agencies in the State Government or Union territory level dealing with CRZ shall be responsible for implementing the CRZ Notification, 2010;
- (b) the Central Government for the purpose of monitoring and enforcement of the CRZ shall notify the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) and State Government or Union Territory CZMA in all the 13 States and Union territories in accordance with the Order of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition No.664 of 1993.
- (c) notwithstanding contained in any other notification issued under Environment (Protection) Act, 1986, the NCZMA, the State or Union territory CZMA, constituted under the Environment (Protection) Act, 1986 shall be responsible for enforcing and monitoring the CRZ Notification, 2010;
- (d) the NCZMA and the SCZMA shall be adequately empowered with the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 to take action against violations of CRZ Notification, 2010;
- (e) the agencies or authorities indicated at items (a) and (b) of paragraph 6.2 shall in exercise of its power and performance of its functions under the Environment (Protection) Act, 1986 issue directions to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions;
- (f) in case where the MoEF, National Coastal Zone Management Authority and State or Union territory CZMA is of the opinion that in view of the likelihood of a great injury to the coastal environment, it is not expedient to provide an opportunity to file

objections against the proposed directions, it may, for reasons to be recorded in writing, issue directions without providing such an opportunity.

7. Classification of the CRZ – For the purpose of conserving and protecting the coastal areas and marine waters, the CRZ area shall be classified as follows, namely:-

(i) CRZ-I,-

A. The areas that are ecologically sensitive and the geomorphological features which play a role in the maintaining the integrity of the coast,-

(a) Mangroves, in case mangrove area is more than 1000 sq mts, a buffer area of 50meters shall be provided;

(b) Corals and coral reefs and associated biodiversity;

(c) Sand Dunes;

(d) Mudflats which are biologically active;

(e) National parks, marine parks, sanctuaries, reserve forests, wildlife habitats and other protected areas under the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) or Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); including Biosphere Reserves;

(f) Salt Marshes;

(g) Turtle nesting grounds;

(h) Horse shoe crabs habitats;

(i) Sea grass beds;

(j) Nesting grounds of birds;

(k) Areas or structures of archaeological importance and heritage sites.

B. The area between Low Tide Line and High Tide Line; and

C. The areas prone for inundation due to sea level rise,-

(ii) CRZ-II,-

The areas that have been developed upto or close to the shoreline.

Explanation.- For the purposes of Item A, B, and C the expression “developed area” is referred to as that area within the municipal limits or in other legally designated urban areas which is already substantially built-up and which has been provided

with drainage and approach roads and other infrastructural facilities, such as water supply and sewerage mains;

(iii) CRZ-III,-

Areas that are relatively undisturbed and those do not belong to either Category-I or II which include coastal zone in the rural areas (developed and undeveloped) and also areas within municipal limits or in other legally designated urban areas, which are not substantially built up.

(iv.) CRZ-IV,-

A. the water area from the Low Tide Line to twelve nautical miles on the seaward side;

B. shall include the water area of the tidal influenced water body from the mouth of the water body at the sea upto the influence of tide which is measured as five parts per thousand during the driest season of the year.

(v) Areas requiring special consideration for the purpose of protecting the critical coastal environment and difficulties faced by local communities,-

A. CRZ area falling within municipal limits of Greater Mumbai;

B. the CRZ areas of Kerala including the backwaters and backwater islands;

C. the Sunderbans region of West Bengal;

D. CRZ areas of Goa.

8. Norms for regulation of activities,-

(i) It shall be ensured that adequate safety measures are in-built or provided for such projects which are proposed to be located in the hazard zone.

(ii) The development or construction activities in different categories of CRZ shall be regulated by concerned authorities at the State or Union Territory level in accordance with the following norms, namely:-

I. CRZ-I,-

(i) no new construction shall be permitted in CRZ-I except,-

(a) projects relating to Department of Atomic Energy;

- (b) pipelines, conveying systems including transmission lines;
 - (c) facilities that are essential for activities permissible under CRZ-I;
 - (d) installation of weather radar for monitoring of cyclones movement and prediction by Indian Meteorological Department;
 - (e) construction of trans harbour sea link and roads on stilts or pillars without affecting the tidal flow of water, between LTL and HTL.
 - (f) development of green field airport at Navi Mumbai shall be undertaken subject to detailed scientific study for incorporating adequate environmental safeguard measures required for neutralizing damage to coastal environment as may be appropriate to the Navi Mumbai region;
- (ii) Between LTL and HTL in areas which are not ecologically sensitive and important the following may be permitted, namely:-
- (a) exploration and extraction of natural gas;
 - (b) construction of dispensaries, schools, public rainshelter, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage which are required for traditional inhabitants living within the biosphere reserves after obtaining approval from concerned CZMA.
 - (c) necessary safety measure shall be incorporated while permitting such developmental activities in the area falling in the hazard zone;
 - (d) salt harvesting by solar evaporation of seawater;
 - (e) desalination plants;
 - (f) storage of non-hazardous cargo such as edible oil, fertilizers and food grain within notified ports;
 - (g) construction of trans harbour sea links, roads on stilts or pillars without affecting the tidal flow of water.

II. CRZ-II,-

- (i) Buildings shall be permitted only on the landward side of the existing road (or roads proposed in the approved CZMP of the area) or on the landward side of existing

authorized structures or on the landward side of the hazard line if, there are no existing authorized structures abutting the plot.

- (ii) Buildings permitted on the landward side of the existing and proposed roads or existing authorized structures shall be subject to the existing local town and country planning regulations including the 'existing' (existing means as existed on 19.2.1991) norms of Floor Space Index or Floor Area Ratio:

Provided that no permission for construction of buildings shall be given on landward side of any new roads (except proposed in the approved CZMP) which are constructed on the seaward side of an existing road:

Provided further that the above restrictions on construction, based on existing roads/authorized structures, roads proposed in the approved CZMP, new roads shall not apply to the housing schemes of State Urban development Authorities implemented in phases for which construction activity was commenced prior to 19.2.1991 in atleast one phase and all relevant approvals from State or local authorities were obtained prior to the 19th February, 1991; in all such cases specific approval of the MoEF would be necessary on a case to case basis;

- (ii) reconstruction of authorized building to be permitted subject with the existing Floor Space Index or Floor Area Ratio Norms and without change in existing use;
- (iii) the design and construction of buildings shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style;
- (iv) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II appended to this notification and facilities for regasification of Liquefied Natural Gas subject to the conditions as mentioned in sub-paragraph (ii) of paragraph 2;
- (v) desalination plants and associated facilities;
- (vi) storage of non-hazardous cargo, such as edible oil, fertilizers and food grain in notified ports;
- (vii) facilities for generating power by non-conventional power sources and associated facilities

III. CRZ-III,-

A. Area upto 200mts from HTL on the landward side is to be earmarked as “No Development Zone”, -

- (i) the No Development Zone shall not be applicable in such area falling within any notified port limits or any notified Special Economic Zones;
- (ii) No construction shall be permitted within this zone except for repairs or reconstruction of existing authorized structure not exceeding existing Floor Space Index, existing plinth area and existing density and for permissible activities under the notification including facilities essential for activities;
- (iv) however, the activities relating to agriculture, horticulture, gardens, pasture, parks, play field, forestry may be permitted in this zone;
- (v) projects relating to Department of Atomic Energy;
- (vi) mining of rare minerals;
- (vii) salt manufacture from seawater;
- (viii) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II;
- (ix) facilities for regasification of liquefied natural gas subject to conditions as mentioned in subparagraph (ii) of paragraph 2;
- (x) facilities for generating power by non conventional energy sources;
- (xi) setting up of desalination plants and associated facilities;
- (xii) weather radars;
- (xiii) construction of dispensaries, schools, public rain shelter, community toilets, bridges, roads, provision of facilities for water supply, drainage, sewerage, crematoria, cemeteries and electric sub-station which are required for the local inhabitants may be permitted on a case to case basis by Central Government or CZMA;
- (xiv) construction of units or auxiliary thereto for domestic sewage, treatment and disposal with the approval of the concerned Pollution Control Board or Committee;

- (xv) facilities required for local fishing communities such as fish drying yards, auction halls, net mending yards, traditional boat building yards, ice plant, ice crushing units, fish curing facilities etc.

B. Area between 200mts to 500mts,-

- (i) development of vacant plot between 200 and 500 mts of HTL is designated areas of CRZ-III with (prior approval of MoEF permitted for construction of hotels or beach resorts for temporary occupation of tourists or visitors subject to the conditions as specified in the guidelines at Annexure-III ;
- (ii) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II;
- (iii) facilities for regasification of liquefied natural gas subject to conditions as mentioned in sub-paragraph (ii) of paragraph 2;
- (iv) storage of non-hazardous cargo such as, edible oil, fertilizers, food grain in notified ports;
- (v) desalination plants and associated facilities;
- (vi) facilities for generating power by non-conventional energy sources;
- (vii) construction or reconstruction of dwelling units permitted so long it is within the ambit of traditional rights and customary uses such as existing fishing villages and goathans.
- (viii) building permission for such construction or reconstruction will be subject to the condition that total number of dwelling units shall not be more than twice the number of existing units; total covered area on all floors shall not exceed 33% of the plot size; the overall height of construction shall not exceed 9mts and construction shall not be more than two floors (ground + one floor);
- (ix) construction is allowed for permissible activities under the notification including facilities essential for such activities;
- (x) an authority designated by the State Government or Union territory Administration may permit construction of public rain shelters, community toilets, water supply drainage, sewerage, roads and bridges and the said Authority may also permit construction of schools and dispensaries for local inhabitants of the area for those

panchayats, the major part of which falls within CRZ if no other area is available for construction of such facilities;

(x) reconstruction or alteration of existing authorised building permitted subject to sub-paragraph (vii), (viii) and (ix);

(xi) in notified Special Economic Zone construction of non polluting industries in the field of Information Technology and other service industries, desalination plants, beach resorts and related recreational facilities essential for promotion of Special Economic Zone as approved in its Master Plan by SEZ Authority may be permitted;

(xii) development of green field airport and related activities at Navi Mumbai.

(IV) In CRZ-IV areas,-

(a) No untreated sewage, effluents or solid waste shall be let of or dumped.

(b) A comprehensive plan for treatment of sewage generating from the city shall be formulated within a period of one year from the date of issue of this notification and be implemented within two years thereafter.

(c) There shall be no restriction on the traditional fishing and allied activities undertaken by local communities.

V. Areas requiring special consideration,-

1. CRZ falling within municipal limits of the Greater Mumbai.

(i) Keeping in view the environmental issues, relating to degradation of mangroves, pollution of creeks and coastal waters, due to discharge of untreated effluents and disposal of solid waste and the need to provide decent housing to the poor section of the people, the Ministry hereby provides special regulation for the CRZ areas of the Greater Mumbai.

(ii) All developmental activities in the CRZ area of the Greater Mumbai shall be regulated as follows, namely:-

A. In CRZ-I areas indicated at sub-paragraph (i) of paragraph 7 of the Notification the following activities only can be taken up:-

(a) Construction of roads, approach roads and missing link roads approved in the Developmental Plan of Greater Mumbai on stilts ensuring that the free flow of tidal

water is not affected, without any benefit of CRZ-II accruing on the landward side of such constructed roads or approach roads.

(b) Twice the number of mangroves destroyed/cut during the construction process shall be replanted.

(c) Within one year of the date of issue of the notification

(1) All mangrove areas shall be mapped and notified as protected forest and necessary protection and conservation measures for the identified mangrove areas shall be initiated.

(2) Solid waste disposal sites shall be identified outside the CRZ area and thereafter within one year the existing convention solid waste sites shall be relocated outside the CRZ area.

(3) An action plan to protect the habitations and structures located on the seaward side of the hazard line shall be launched.

(iii) In CRZ-II areas-

(a) The development or redevelopment shall continue to be in accordance with the norms laid down in the Town and Country Planning Regulations as they existed on the date of issue of the notification dated 19.2.1991, unless specified otherwise in the instant notification.

(b) SLUM REHABILITATION SCHEMES,-

(1) In the Greater Mumbai area there are large slum clusters with lakhs of families residing therein and the living conditions in these slums are deplorable and the civic agencies are not able to provide basic infrastructure such as drinking water, electricity, roads, drainage etc. because the slums come up in an unplanned and congested manner.

(2) The slums in the coastal area are at great risk in the event of cyclones, storm surges or tsunamis, in view of the difficulties in providing rescue, relief and evacuation.

(3) To provide a safe and decent dwelling to the slum dwellers, the State Government may implement slum redevelopment schemes directly or through its parastatal agencies like Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA).

Shivshahi Punarvasan Prkalp Limited (SPPL), Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) etc.:

Provided that,-

- (i) Such redevelopment schemes shall be undertaken directly or through joint ventures or through public private partnerships or other similar models ensuring that the stake of the State Government or its parastatal entities shall be not less than 51%;
- (ii) the Floor Space Index or Floor Area Ratio for such redevelopment schemes shall be in accordance with the Town and Country Planning Regulations prevailing as on the date on which the project is granted approval by the competent authority;
- (iii) it shall be the duty of the project proponent undertaking the redevelopment through conditions (i) above along with the State Government to ensure that all legally regularized tenants are provided houses in situ or as per norms laid down by the State Government in this regard.

(c) REDEVELOPMENT OF DILAPIDATED, CESSSED AND UNSAFE BUILDINGS: In the Greater Mumbai, there are, also a large number of old and dilapidated, cessed and unsafe buildings in the CRZ areas and due to their age these structures are extremely vulnerable and disaster prone. Therefore there is an urgent need for the redevelopment or reconstruction of these identified buildings. These projects shall be taken up subject to the following conditions and safeguards:

- (1) Such redevelopment or reconstruction projects shall be allowed to be taken up involving the owners of these buildings either alone or with private developers in accordance with the prevailing Regulation, directly or through joint ventures or through other similar models.
- (2) The Floor Space Index or Floor Area Ratio for such redevelopment schemes shall be in accordance with the Town and Country Planning Regulations prevailing as on the date on which the project is granted approval by the competent authority.

(3) Suitable accommodation to the original tenants of the specified buildings shall be ensured during the course of redevelopment or reconstruction of the buildings by the project proponents, undertaking the redevelopment through condition (1) above.

(d) Notwithstanding anything contained in the instant Notification, the developmental activities for slums and for dilapidated, cessed and unsafe buildings as specified at paras (b) and (c) above shall be carried out in an accountable and transparent manner by the project proponents mentioned therein which shall include the following measures, wherever applicable;-

1. Applicability of the Right to Information Act, 2005 to all redevelopment or reconstruction projects granted clearance by the Competent Authorities.
2. Performance and fiscal auditing by the office of the Comptroller and Auditor General of India.
3. Setting up of a High Level Oversight Committee for periodic review by the Government of Maharashtra which shall include eminent representatives of various Stakeholders, like Architects, Urban Planner, Engineers, and Civil Society, besides the local urban bodies, the State Government and the Central Government.

(e) In order to protect and preserve the 'green lung' of the Greater Mumbai area, all open spaces, parks, gardens, playgrounds indicated in development plans within CRZ-II shall be categorized as CRZ-III, that is, 'no development zone'. However Floor Space Index upto 15% shall be allowed restricted to construction of civic amenities, stadium, gymnasium, etc., meant for recreational or sports related activities. Residential or commercial use of such open spaces shall not be permissible.

(f) Reconstruction and repair works of the dwelling units belonging to fisher communities and other local communities identified by the State Government, shall be considered and granted permission by the Competent Authorities on a priority basis.

2. CRZ for Kerala

- (i) All the islands in the backwaters of Kerala shall be covered under the CRZ notification.

- (ii) The islands within the backwaters shall have 50mts CRZ area from the High Tide Line on the landward side.
- (iii) Within 50mts from the HTL of these backwater islands existing dwelling units of local communities can be repaired or reconstructed and no new constructions shall be carried out.
- (iv) Beyond 50mts from the HTL on the landward side of backwater islands, dwelling units of local communities can be constructed with the permission of the local panchayat.
- (v) Foreshore facilities such as fishing jetty, fish drying yards, net mending yard, fishing processing by traditional methods, boat building yards, ice plant, boat repairs etc., can be taken up within 0-50mts of these backwater islands.

3. CRZ of Goa.-

- (i) The Government of Goa shall survey and map the fishing villages all along the Goa coast. Facilities required for fishing and fishery allied activities such as traditional fish processing yards, boat building or repair yards, net mending yards, ice plants, ice storage, auction hall, jetties shall be provided.
- (ii) Reconstruction, repair works of the structures of local communities shall be permissible in CRZ.
- (iii) The eco sensitive low lying areas which are influenced by tidal action known khazan lands shall be mapped.
- (iv) The mangroves along such khazan land shall be protected and a management plan for the khazan land prepared and no developmental activities shall be permitted in the khazan land.
- (v) Sand dunes, beach stretches along the bays and creeks shall be surveyed and mapped. No activity shall be permitted on such sand dune areas.
- (vi) The beaches such as Mandrem, Morjim, Galgiba and Agonda has been designated as turtle nesting sites and protected under the Wildlife Protection Act, 1972 and these areas shall be surveyed and management plan prepared for protection of these turtle nesting sites.
- (vii) No developmental activities shall be permitted in the turtle breeding areas referred to in sub-paragraph (vi).

4. CRZ for Sunderbans and other ecologically important areas.-

- (a) The entire Sunderbans Bio-sphere and other identified ecologically important areas such as Gulf of Khambat and Gulf of Kutch in Gujarat, Malvan, Achra-Ratnagiri, in Maharashtra, Karwar and Coondapur in Karnataka, Vembanad in Kerala, Bhaitarkanika in Orissa, Coringa, East Godavari and Krishna in Andhra Pradesh shall be declared as Critically Vulnerable Coastal Areas (CVCA).
- (b) An integrated management plan shall be drawn up within a period of one year from the date of issue of this notification keeping in view conservation and management of the mangroves, needs of local communities such as, dispensaries, schools, public rain shelters, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage and the impact of sea level rise.
- (c) The Integrated Management Plan (IMP) for Sunderbans and for other ecologically important areas shall be approved and notified by the Ministry after obtaining the views of the public in accordance with the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- (d) The notified IMP shall be implemented in a time bound manner for which assistance shall be provided by the State Government and Central Government.
- (e) Till such time the IMP are approved and notified, construction of dispensaries, schools, public rain shelters, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage which are required for traditional inhabitants shall be permitted on a case to case basis, by the CZMA.

[F. No. 11-83/2005-IA-III]

J. M. MAUSKAR, Addl. Secy.

ANNEXURE I**GUIDELINES FOR PREPARATION OF COASTAL ZONE MANAGEMENT PLANS****I. A. Demarcation of High Tide Line**

1. Demarcation of High Tide Line (HTL) and Low Tide Line (LTL) shall be carried out by one of the agencies authorised by MoEF based on the recommendations of the National Centre for Sustainable Coastal Zone (NCSCZ).
2. Demarcation of the High Tide Line or LTL shall be made on the Coastal Zone Management (CZM) Maps of scale 1:25,000 prepared by the agencies identified by the Central Government.
3. Local level CZM Maps shall be prepared for use of officials of local bodies for determination of the CRZ.
4. The local level CZM Maps shall be prepared on a Cadastral scale in accordance with the CZM Maps approved by the Central Government.

B. Preparation of CZM Maps

5. Base Maps of 1:25,000 scale shall be acquired from the Survey of India (SOI) and wherever 1:25,000 maps are not available, 1:50,000 maps shall be enlarged to 1:25,000 for the purpose of base map preparation and these maps will be of the standard specification given below:

Unit	:	7.5 minutes X 7.5minutes
Numbering	:	Survey of India Sheet Numbering System
Horizontal Datum	:	Everest or WGS 84
Vertical Datum	:	Mean Sea Level (MSL)
Topography	:	Topography in the SOI maps will be updated using latest satellite imageries or aerial photographs

6. The High Water Level (HWL) and Low Water Level (LWL) marked on the Base maps will be transferred to the CZM maps.
7. Coastal geomorphological signatures in the field or satellite imageries or aerial photographs will be used for appropriate adjustment, in the HWL or LWL for demarcating HTL or LTL in accordance with the CRZ Notification.
8. The following geomorphological features shall be considered while demarcating in HTL or LTL:

Landward (monsoonal) crest in the case of sandy beaches

Rocks, Headlands, Cliffs

Seawalls or revetments or embankments

9. 500 meter and 200 metre lines will be demarcated with respect of HTL.
10. HTL (as defined in the CRZ Notification) and LTL shall also be demarcated in the CZM maps along the banks of tidal influenced inland water bodies with the help of the geomorphological signatures or features.
11. Classification of different coastal zones shall be done as per the CRZ Notification
12. Standard national or international colour codes shall be used to highlight sub-classification of data.

C. Local level CZM Maps

Local level CZM Maps are for the use of local bodies and other agencies to facilitate implementation of the Coastal Zone Management Plans

13. Cadastral (village) maps in 1:3960 or the nearest scale, shall be used as the base maps.
14. These maps are available with revenue Authorities and are prepared as per standard norms.
15. HTL (as defined in the CRZ Notification) and LTL will be demarcated in the cadastral map based on detailed physical verification using coastal geomorphological signatures or features in accordance with the CZM Maps approved by the Central Government.
16. 500metre and 200metre lines shall be demarcated with respect to the HTL thus marked.
17. HTL (as defined in the CRZ Notification, 1991) and LTL will also be demarcated along the banks of tidal influenced inland water bodies with the help of geomorphological signatures or features.
18. Classifications shall be transferred into local level CZM maps from the CZM Maps.
19. Symbols will be adopted from CZM Maps.
20. Colour codes as given in CZM Maps shall be used.
21. Demarcation of cadastral maps will be done by local agencies approved by the Central Government. The local agencies shall work under the guidance of the concerned State Government or Union Territory Coastal Zone Management Authorities.

D. Hazard mapping:-

II. Classification of CRZ areas

1. The CZM Maps shall be prepared in accordance with para 5 of the CRZ Notification demarcating CRZ I, II, III, IV and V.
2. The CZM Maps shall clearly demarcate the land use plan of the area and lists out the CRZ-I areas. All the CRZ-I areas listed under para 7(I)A and B shall be clearly demarcated and colour codes given so that each of the CRZ-I areas can be clearly identified.

3. Buffer zone along mangrove areas of more than 1000sq mts shall be stipulated with a different colour distinguishing from the mangrove area.
4. The buffer zone shall also be classified as CRZ-I area.
5. The hazard line to be drawn up by MoEF shall be superimposed on the CZM maps in 1:25,000 scale and also on the cadastral scale maps.
6. The CRZ-II areas shall be those areas which have been substantially built-up with a ratio of built-up plots to that of total plots is more than 50%.
7. In the CRZ-III areas, the fishing villages, common properties of the fishermen communities, fishing jetties, ice plants, fish drying platforms or areas infrastructure facilities of fishing and local communities such as dispensaries, roads, schools, etc., shall be indicated on the cadastral scale maps.
8. The water areas of CRZ IV shall be demarcated and clearly demarcated if the water body is sea, lagoon, backwater, creek, bay, estuary and for such classification of the water bodies the terminology used by Naval Hydrographic Office shall be relied upon.
9. The fishing Zones in the water bodies and the fish breeding areas shall be clearly marked.
10. The water area shall be demarcated indicating the pollution levels as per Central Pollution Control Board standards on water quality.
11. In the CRZ V areas the land use maps shall be superimposed on the Coastal Zone Management Plan and clearly demarcating the CRZ I, II, III, IV.
12. The existing authorized developments on the sea ward side shall be clearly demarcated.
13. The features like cyclone shelters, rain shelters, helipads and other infrastructure including road network may be clearly indicated on the CZM Maps for the purpose of rescue and relief operations during cyclones, storms, tsunami etc.

III. Revision of Coastal Zone Management Plans

1. Whenever there is a doubt the concerned State or Union territory Coastal Zone Management Authority shall refer the matter to the National Centre for Sustainable Coastal Zone who shall verify the CZMP based on latest satellite imagery and ground truthing.
2. The rectified map would be submitted to MoEF for its record.
3. Keeping in view the dynamic nature of the coast the CZM Maps shall be revised once in five years.

IV. Public Views on the CZMP.

- a) The draft CZMPs prepared shall be given wide publicity and suggestions and objections received in accordance with the Environment (Protection) Act, 1986.

- b) Based on the suggestions and objections received the CZMPs shall be revised and approval of MoEF shall be obtained.
- c) The approved CZMP shall be put up on the website of MoEF, concerned website of the State, Union Territory CZMA and hard copy made available in the panchayat office, District collector office etc.

Annexure-II

[See paragraph 3(ii)(b)]

List of petroleum and chemical products permitted for storage in [CRZ except CRZ-I(i)]

- (i) Crude oil;
- (ii) Liquefied Petroleum Gas;
- (iii) Motor spirit;
- (iv) Kerosene;
- (v) Aviation fuel;
- (vi) High speed diesel;
- (vii) Lubricating oil;
- (viii) Butane;
- (ix) Propane;
- (x) Compressed Natural Gas;
- (xi) Naphtha;
- (xii) Furnace oil;
- (xiii) Low Sulphur Heavy Stock;
- (xiv) Liquefied Natural Gas;
- (xv) Fertilizers and raw materials for manufacture of fertilizers.

Annexure-III**Guidelines for development of beach resorts or hotels in the designated areas of CRZ-III and CRZ-II for temporary occupation of tourist or visitors with prior approval of the Ministry of Environment and Forests**

I. Construction of beach resorts or hotels with prior approval of MoEF in designated areas of SPCZ-II and III for temporary occupation of tourist or visitors shall be subject to the following conditions, namely:-

- (a) The project proponent shall not undertake any construction within 200 metres in the landward side of High Tide Line and within the area between Low Tide Line and High Tide Line;
- (b) The proposed constructions shall be beyond the hazard line or 200mts from the High Tide Line whichever is more;
- (c) live fencing and barbed wire fencing with vegetative cover may be allowed around private properties subject to the condition that such fencing shall in no way hamper public access to the beach;
- (d) no flattening of sand dunes shall be carried out;
- (e) no permanent structures for sports facilities shall be permitted except construction of goal posts, net posts and lamp posts;
- (f) Construction of basement may be allowed subject to the condition that no objection certification is obtained from the State Ground Water Authority to the effect that such construction will not adversely affect the flow of groundwater in that area;
- (g) the State Ground Water Authority shall take into consideration the guidelines issued by Central Government before granting such no objection certificate;
- (h) though no construction is allowed in the no development zone for the purposes of calculation of Floor Space Index, the area of entire plot including the portion which falls within the no development zone shall be taken into account;
- (i) the total plot size shall not be less than 0.4 hectares and the total covered area on all floors shall not exceed 33 percent of the plot size i.e., the Floor Space Index shall not exceed 0.33 and the open area shall be suitably landscaped with appropriate vegetal cover;

- (j) the construction shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style;
- (k) the overall height of construction upto the highest ridge of the roof, shall not exceed 9metres and the construction shall not be more than two floors (ground floor plus one upper floor);
- (l) groundwater shall not be tapped within 200metre of the High Tide Line; within the 200metre 500metres zone it can be tapped only with the concurrence of the Central or State Ground Water Board;
- (m) extraction of sand, leveling or digging of sandy stretches except for structural foundation of building, swimming pool shall not be permitted within 500metres of the High Tide Line;
- (n) the quality of treated effluents, solid wastes, emissions and noise levels etc., from the project area must conform to the standards laid down by the competent authorities including the Central or State Pollution Control Board and under the Environment (Protection) Act, 1986;
- (o) necessary arrangements for the treatment of the effluents and solid wastes must be made and it must be ensured that the untreated effluents and solid wastes are not discharged into the water or on the beach; and no effluent or solid waste shall be discharged on the beach;
- (p) to allow public access to the beach, atleast a gap of 20metres width shall be provided between any two hotels or beach resorts; and in no case shall gaps be less than 500metres apart; and
- (q) if the project involves diversion of forestland for non-forest purposes, clearance as required under the Forest (Conservation) Act, 1980 shall be obtained and the requirements of other Central and State laws as applicable to the project shall be met with; and
- (r) approval of the State or Union territory Tourism Department shall be obtained.

II. In ecologically sensitive areas (such as marine parks, mangroves, coral reefs, breeding and spawning grounds of fish, wildlife habitats and such other area as may be notified by the Central or State Government Union territories) construction of beach resorts or hotels shall not be permitted

Annexure-IV**Form-I for seeking clearance for project attracting CRZ Notification**

Basic information:

Name of the Project:-

Location or site alternatives under consideration:-

Size of the project (in terms of total area) :-

CRZ classification of the area :-

Expected cost of the project:-

Contact Information:-

(II) Activity

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Details of CRZ classification as per the approved Coastal Zone Management Plan?		
1.3	Whether located in CRZ-I area?		
1.4	The distance from the CRZ-I areas.		
1.5	Whether located within the hazard zone as mapped by MoEF?		
1.6	Whether the area is prone to cyclone, tsunami, tidal surge, subduction, earthquake etc.?		
1.7	Whether the area is prone for saltwater ingress?		
1.8	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.9	Creation of new land uses?		
1.10	Pre-construction investigations e.g. bore hole, soil testing?		
1.11	Construction works?		
1.12	Demolition works?		
1.13	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
1.14	Above ground buildings, structures or		

	earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.15	Underground works including mining or tunneling?		
1.16	Reclamation works?		
1.17	Dredging/reclamation/land filling/disposal of dredged material etc.?		
1.18	Offshore structures?		
1.19	Production and manufacturing processes?		
1.20	Facilities for storage of goods or materials?		
1.21	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
1.22	Facilities for long term housing of operational workers?		
1.23	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
1.24	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?		
1.25	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
1.26	New or diverted transmission lines or pipelines?		
1.27	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
1.28	Stream and river crossings?		
1.29	Abstraction or transfers of water from ground or surface waters?		
1.30	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		
1.31	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
1.32	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
1.33	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
1.34	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
1.35	Introduction of alien species?		
1.36	Loss of native species or genetic diversity?		
1.37	Any other actions?		

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):

S. No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		
2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		

2.4	Construction material – stone, aggregates, sand/soil (expected source – MT)		
2.5	Forests and timber (source – MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		
4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		
4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		

4.11	Other solid wastes		
------	--------------------	--	--

Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		
5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		

7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g., floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	Lead to development of supporting. ilities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.: Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.) housing development extractive industries supply industries other		
9.2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

III. Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological,		

	landscape, cultural or other related value		
2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, schools, places of worship, community facilities)		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources (ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing legal environmental standards are exceeded)		
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)		
